PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-02 ● अंक- 02 ● भिलाई, बुधवार 15 जुलाई 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

डांडी चौक पर पुलिस की चेतक सहित तीन बाइकों की टक्कर

हरिद्वार। पथरी थाना क्षेत्र के डांडी चौक पर सोमवार को सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस की चेतक बाइक पर सवार एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घायल कांस्टेबल का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार, शाम मनोज कुमार (35) निवासी फेरुपुर थाना पथरी अपनी मोटरसाइकिल पर डांडी चौकी की तरफ जा रहे थे, जबकि अजय (22) निवासी हौजखेड़ी सहारनपुर यूपी भी बाइक पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान चौराहे पर पुलिस चेतक बाइक पर कांस्टेबल सुशील कुमार भी आ रहे थे। चौराहे पर पहुंचते ही तीनों मोटरसाइकिलों की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

बच्ची के यौन शोषण का आरोपी सुरक्षा गार्ड पुलिस हिरासत में भेजा गया

मुंबई । दक्षिण मुंबई के पायधुनी (दाना बंदर) इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस मामले में गिरफ्तार सुरक्षा गार्ड को पॉक्सो अदालत ने 18 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, घटना 12 जुलाई को उस समय हुई, जब करीब 7 वर्षीय बच्ची आवासीय भवन के वॉशरूम में गई थी। आरोप है कि उसी इमारत में तैनात सुरक्षा गार्ड भी वॉशरूम में पहुंचा और बच्ची का यौन शोषण किया। घटना में बच्ची घायल हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पायधुनी पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ समय के लिए मुख्य सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा।

नागपुर में बाघ को नजदीक देखकर पिता ने बेटे के साथ बांध में लगाई छलांग

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां बाघ को नजदीक देखकर एक पिता ने बेटे के साथ बांध में छलांग लगा दी। डूबने की वजह से पिता और बेटे की मौत हो गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। नागपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। नागपुर से 50 किलोमीटर दूर डेवलापार क्षेत्र में पिता और पुत्र बांध के पास अपनी खेती में काम करने और मछली पकड़ने के लिए गए थे। उस दौरान संजय उइके और उनके रिश्तेदार भी वहां पर मौजूद थे। तभी संजय उइके ने देखा कि एक बाघ उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है।

सक्ती प्लांट दुर्घटना पर विधानसभा में हंगामा...

भूपेश ने कहा-किसी और को बिकवाने के चक्कर में अनिल अग्रवाल के खिलाफ करवाई एफआईआर..

रायपुर। संवाददाता

सक्ती स्थित प्लांट में बॉयलर गिरने से 25 लोगों की मौत का मामला आज विधानसभा में जमकर गूंजा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि किसी अन्य व्यक्ति को प्लांट बिकवाने के मकसद से प्लांट के वर्तमान मालिक अनिल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर करवाई गई। सत्ता पक्ष ने बघेल की इस बात का जमकर विरोध किया। सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए सारे कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से वाक आउट कर गए। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत का सवाल था कि जनवरी 2024 से मई 2026 की अवधि में प्रदेश में कितनी गंभीर प्रकृति की औद्योगिक दुर्घटनाएं हुईं दुर्घटना का कारण क्या था, मृतकों की संख्या कितनी थी, मुआवजा राशि कितनी दी गई, दुर्घटनाओं के संबंध में किनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई दुर्घटना वाले उद्योगों का सेफ्टी ऑडिट कब-कब किसके किसके व्दारा किया गया जांच के निष्कर्ष क्या रहेवाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की ओर से जो जवाब आया उन पर डॉ. महंत ने और भी सवाल खड़े किए। डॉ. महंत ने कहा कि सक्ती में औद्योगिक

संयंत्र में 25 लोगों की मौत हुई एवं 7 घायल हुए। सरकार व्दारा इस दुर्घटना के लिए दोषी लोगों की जो संख्या बताई जाती रही है वह सत्य नहीं है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि

उस मामले में डभरा पुलिस थाने में उद्योग के निदेशक अनिल अग्रवाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। डॉ. महंत ने कहा कि सरकार अनिल अग्रवाल का नाम क्यों छिपाना चाहती है। विधानसभा की पुस्तिका में आए जवाब में तो उनके नाम का उल्लेख नहीं है। क्या इसलिए नहीं है कि कोरबा में भी उनका प्लांट है। अनिल अग्रवाल को पकड़ने क्या कदम उठाए गए हैं मंत्री देवांगन ने कहा कि इस मामले में पुलिस विवेचना जारी है। महंत ने कहा कि विवेचना से मतलब कहीं लेन-देन से तो नहीं है! मंत्री ने कहा कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव ने कहा कि उद्योगपति खोजे नहीं मिल रहे हैं। गरीब को पीटकर अंदर कर दिया जाता है। दोषी लोग कब सलाखों के पीछे जाएंगे।

छत्तीसगढ़ की नगर निगमों में जोन कमिश्नर के पद 26, कार्यरत 28-शेषराज

रायपुर। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक श्रीमती शेषराज हरवंश की ओर से लगाए गए सवालों पर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) अरुण साव ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ की नगर निगमों में जोन कमिश्नर के 26 पद स्वीकृत हैं, जबकि कार्यरत 28 हैं। कांग्रेस विधायक श्रीमती शेषराज हरवंश की ओर से सवाल लगा था कि राज्य के नगर पालिक निगमों में से प्रत्येक में कितने-कितने जोन कमिश्नर कार्यरत हैं जोन कमिश्नर के स्वीकृत पद, इस पद के लिये निर्धारित योग्यताएं तथा वेतन-मान क्या-क्या हैं इस पद के लिये चयन हेतु क्या नियम हैं जोन कमिश्नरों को किस पदाधिकारी की, किन-किन शक्तियों का, किसके व्दारा प्रत्यायोजन किया गया है तथा इनके कर्तव्य क्या निर्धारित हैं जोन कमिश्नर की सेवाएं किन नियमों से शासित होती हैं उप मुख्यमंत्री अरूण साव की ओर से जवाब आया कि रायपुर नगर निगम में जोन कमिश्नरों के स्वीकृत पद 10 व कार्यरत 10, बिलासपुर नगर निगम में स्वीकृत पद 6 व कार्यरत 8, भिलाई नगर निगम में स्वीकृत पद 6 व कार्यरत 6, कोरबा नगर निगम स्वीकृत पद 4 व कार्यरत 4- इस तरह कुल 26 जोन कमिश्नरों के स्वीकृत पद हैं

महाराष्ट्र में सियासी हलचल

आखिर एनसीपी की प्रमुख कैसे बनीं सुनेत्रा पवार....?

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी अजित पवार गुट में पार्टी लीडरशिप को लेकर राजनीतिक घमासान सामने आया है। सुनेत्रा पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं और इस बार फिर से पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने वकील के जरिये सीधे नोटिस भेजकर सवाल खड़ा किया है। नौ जुलाई को उन्होंने यह नोटिस जारी किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया दोबारा कराने की मांग की है। यह नोटिस पार्टी की अध्यक्ष सुनेत्रा पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और पार्टी सचिव बृजमोहन श्रीवास्तव को भेजी गई है। इस नोटिस में 26-02-2026 को हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया को अवैध बताते हुए उसे रद्द करने और दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है। इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अधिकारी नियुक्त करके उनके माध्यम से चुनाव कराया जाए।

पीएम मोदी से मांगा मिलने का समय

माइलेज कम तो दाम भी कम हो-केजरीवाल की ई20 पेट्रोल पर केंद्र सरकार से अपील....

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ई20 पेट्रोल की दाम कम की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ई20 ईंधन की कीमतों में कटौती की मांग करते हुए तर्क दिया कि इसकी माइलेज कम होने के कारण इसके दाम भी कम होने चाहिए। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'मैंने प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन किया है कि ई20 के दाम कम होने चाहिए क्योंकि ई20 की माइलेज कम है तो उसके दाम भी कम होने चाहिए। मैंने उनसे मिलने का समय भी मांगा है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जो-जो लोग इन सभी से दुखी हैं, वे अपनी वीडियो बना-बनाकर सोशल मीडिया पर डालें क्योंकि यह सरकार इतनी आसानी से हमारी बात नहीं सुनेगी।' केजरीवाल ने ई20 ईंधन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने देशभर में लोगों की बढ़ती परेशानी को रेखांकित करते हुए दो प्रमुख मांगें रखी हैं। पत्र में केजरीवाल ने लिखा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए। पूरे देश में लोग ई20 पेट्रोल से नाराज हैं। वाहन मालिकों का कहना है कि ई20 भरने के बाद वाहनों का माइलेज काफी कम हो गया है

और इंजन के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। 1. हर पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल (ई0 या ई10) और ई 20 दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार ईंधन चुन सकें। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा है ताकि वे जनता के अनुभवों और तकनीकी समस्याओं को विस्तार से बता सकें। उन्होंने कहा, 'मैं जनता के बीच गया हूं और उनकी समस्याएं सुनी हैं।' अरविंद केजरीवाल ने आज स्टॉप श्र20 पेट्रोल ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान शुरू किया। इस दौरान केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार बिना पूरी तैयारी के ई20 पेट्रोल देश पर थोप रही है, जबकि लाखों वाहन मालिक माइलेज घटने, इंजन में खराबी और बढ़ते खर्च की शिकायत कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार लोगों की चिंताओं को सुनने के बजाय सब कुछ सामान्य बताने में लगी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए लोग प्रधानमंत्री के नाम याचिका पर हस्ताक्षर कर अपनी आवाज दर्ज करा सकते हैं।

जब मुख्य ट्रस्ट बना तब वैकेंसी क्यों नहीं निकाली

भर्ती केवल औपचारिकता है पहले से तय है सब कुछ

नई दिल्ली/ एजेंसी

अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की चोरी और सुरक्षा चूक की एसआईटी जांच के बीच शुरू हुई मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया अब विवादों के घेरे में आ गई है। ज्योतिष्पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तीखा हमला बोला है। शंकराचार्य ने इस पूरी कवायद को जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा बताते हुए कहा कि ट्रस्ट केवल

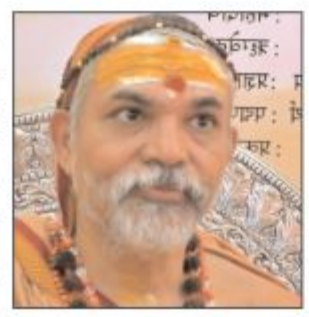

लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। उन्होंने मौजूदा ट्रस्ट पर पारदर्शिता की कमी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरी कमेटी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग कर दी है, जिससे धार्मिक और प्रशासनिक गलियारों में भारी हड़कंप मच गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीईओ पद के लिए जारी किए गए विज्ञापन और कड़े मापदंडों की टाइमिंग पर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने गरजते हुए पूछा कि जब शुरुआत में मुख्य राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया जा रहा था, तब इस तरह की कोई ओपन वैकेंसी या नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया था ?शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि अब जब करोड़ों की चोरी का मामला खुलकर देश के सामने आ गया है,।

विवादित बयान पर उमर अब्दुल्ला को सात दिनों का अल्टीमेटम, माफी मांगें नहीं तो 100 करोड़ का मानहानि का केस

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भाजपा की ओर से 100 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे की चेतावनी दी गई है। भाजपा की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस पर वकील परिमोक्ष सेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए रिश्वत के आरोप पूरी तरह झूठे, निराधार और मानहानिकारक हैं। यदि सात दिनों के भीतर मुख्यमंत्री अपनी टिप्पणी वापस लेकर लिखित माफी नहीं मांगते हैं, तो उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के साथ-साथ 100 करोड़ रुपए का दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा।

पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा एक्शन

मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ वारंट जारी...

नई दिल्ली। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया है। इसके बाद कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद हाफिज सईद को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही इस आदेश के

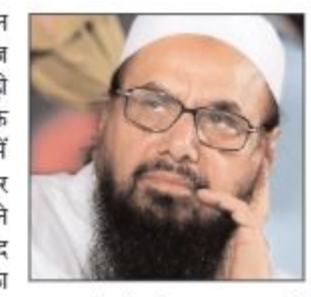

बाद सईद के खिलाफ ट्रायल भी शुरू हो सकता है।हाफिज सईद के खिलाफपहलगाम हमले को लेकर मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया है। एनआईए ने हाफिज सईद के खिलाफ 60 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी है। मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाफिज सईद को हमले का मास्टरमाइंड बताया है। एनआईए की ओर से कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में है। उसे भारत लाना फिलहाल संभव नहीं है। एनआईए ने कोर्ट से कानून के तहत हाफिज सईद की गैरमौजूदगी में उसके खिलाफ ट्रायल चलाने की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। एनआईए की दलीलों से सहमति जताते हुए कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

रायपुर शहर के जल संकट पर चंद्राकर, मूणत व सोनी ने अपनी ही सरकार को घेरा...

जल मिशन में चौबीसों घंटे पानी का कोई प्रावधान नहीं-साव

रायपुर। संवाददाता

विधानसभा में आज रायपुर शहर के जल संकट को लेकर भाजपा विधायकगण अजय चंद्राकर, राजेश मूणत एवं सुनील सोनी ने अपनी ही सरकार को जमकर घेरा। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि जल मिशन में स्मार्ट सिटी का पैसा लगाकर भारी करप्शन किया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट किया अमृत जल मिशन के तहत चौबीसों घंटे पानी देने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का सवाल था कि रायपुर नगर निगम अंतर्गत अमृत मिशन कब लागू हुआ और कब कार्य पूर्ण सम्पादित हुआ पूरे कार्य में कितनी लागत आई इस योजना से निगम क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोगों को पेयजल उपलब्ध हुआ जल जीवन मिशन की भौतिक और वित्तीय उपलब्धि, कार्यपूर्णता की समयावधि क्या है 15 जून 2026 की स्थिति में उक्त दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन होने के बाद रायपुर निगम क्षेत्र के कितने प्रतिशत लोगों को नल से शुद्ध पेयजल 24 घण्टे उपलब्ध हो रहा है यदि पूरी आबादी को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके क्या कारण हैं दोषी कौन है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 (15 जून, 2026 की स्थिति) में रायपुर शहर अंतर्गत पानी टैंकर से पानी सप्लाई में कितनी राशि, किस मद से व्यय हुई उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद भी टैंकर से पानी सप्लाई के क्या कारण

हैं उप मुख्यमंत्री अरूण साव की ओर से जवाब आया कि रायपुर नगर निगम अंतर्गत अमृत मिशन योजना 2016 में प्रारंभ तथा 2025 में पूर्ण हुई। योजना के जल प्रदाय घटक के कार्यों को पूर्ण करने में कुल 4 अरब 27 करोड़ 37 लाख 23 हजार की लागत आई। इस योजना के तहत 20 वार्ड में निवासरत जनसंख्या को पूर्ण रूप से तथा 25 वार्ड में निवासरत जनसंख्या को आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत रायपुर नगर निगम में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं है। रायपुर नगर निगम व्दारा क्रियान्वित अमृत मिशन योजना में 24 घण्टे निरंतर जलापूर्ति का प्रावधान नहीं था। वर्तमान में जलागारों से सुबह व शाम जलापूर्ति की जाती है। रायपुर शहर में पेयजल व्यवस्था अमृत मिशन के अलावा अन्य योजनाओं, स्मार्ट सिटी मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से भी की गई है। वर्तमान में कुल 3 लाख 42 हजार मकानों में से कुल 2 लाख 21 हजार मकानों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जनसंख्या के पृथक से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। शहर के तीव्र विस्तार एवं निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण सम्पूर्ण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चूंकि ढांचागत विकास वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर है, अत: शत-प्रतिशत क्षेत्र कवर न होने के लिए कोई विशिष्ट अधिकारी दोषी नहीं है।टैंकर सप्लाई हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 58.35 लाख, 2024-25 में 168.46 लाख, 2025-26 में 206.98 लाख तथा 2026-27 (15 जून 2026 की स्थिति में) में 211.54 लाख का व्यय जल संकट मद से किया गया है। शहर के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ भूजल स्तर में गिरावट आना इसका मुख्य कारण है। अजय चंद्राकर ने कहा कि जल मिशन के कार्य से स्मार्ट सिटी को जोड़कर 158 करोड़ खर्च करते हुए भारी करप्शन किया गया है। रायपुर शहर के किसी भी वार्ड में 24 घंटे सातों दिन पानी नहीं मिल रहा है। मेरे हिसाब से रायपुर शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए तकनीकी रूप से दक्ष विशेषज्ञ पदस्थ नहीं हैं। सुनील सोनी ने कहा कि पूरी गर्मी में रायपुर शहर में जहां-जहां पानी की टंकियां थी।

CMYK

ग्राम गुजरा में जिला स्तरीय 'शाला प्रवेश उत्सव' का आयोजन किया गया

दल्लीराजहरा। डौंडी विकासखंड के ग्राम गुजरा में जिला स्तरीय 'शाला प्रवेश उत्सव' का भव्य आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सांसद भोजराज नाग शामिल हुए। उन्होंने नवप्रवेशी स्कूली बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया और उन्हें मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर सांसद नाग ने विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और गणवेश (यूनिफॉर्म) वितरित किए साथ ही, 'सरस्वती साइकिल योजना' के अंतर्गत छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गईं, ताकि उन्हें स्कूल आने-जाने में सुविधा हो सके।

कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण 'न्यौता भोज' रहा, जहां सांसद ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और उनसे संवाद किया। इस गरिमामयी समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, ग्रामीण और स्कूली बच्चे उपस्थित थे।

विधानसभा में संगीता सिन्हा का सरकार पर हमला: भाजपा नेताओं के अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं, गरीबों के घर तोड़े जा रहे

बेदखली वारंट जारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का लगाया आरोप, मंत्री टंकराम वर्मा और जिला प्रशासन पर संरक्षण देने का दावा

बालोद। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में संजारी-बालोद विधायक एवं प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बालोद जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बेदखली वारंट जारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। विधायक संगीता सिन्हा ने सदन में कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रदीप कुमार साहू के खिलाफ 7 सितंबर 2025 को बेदखली वारंट जारी

किया गया था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। इसी प्रकार दुर्गानंद साहू के खिलाफ 11 दिसंबर 2025 को बेदखली वारंट जारी होने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि पलारी, बोड़रा, बालोद और नकटी सहित कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। नकटी में तो 85 मकानों को तोड़ दिया गया, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ वैधानिक आदेश जारी हैं, उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। संगीता सिन्हा ने दावा किया कि उनके पास इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से संबंधित दस्तावेज, तहसीलदार द्वारा जारी बेदखली आदेश, एसडीएम का बेदखली वारंट, कलेक्टर तथा संभागायुक्त (कमिश्नर) के आदेश की प्रतियां उनके पास हैं। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है।

बेदखली वारंट वाले सभी मामलों में की जाए तत्काल कार्रवाई

सदन में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदीप साहू नगर पंचायत के भाजपा अध्यक्ष हैं और दुर्गानंद साहू जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। इसी कारण उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश के मंत्री टंकराम वर्मा इन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। विधायक ने सरकार से सवाल किया कि जब जिला प्रशासन अन्य स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है, तब भाजपा नेताओं के मामलों में अलग रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। उन्होंने इसे प्रशासनिक भेदभाव और दोहरे मापदंड का उदाहरण बताया। संगीता सिन्हा ने यह भी कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन से सूचना मांगी थी कि अतिक्रमण हटाने के संबंध में कब-कब और किन-किन लोगों से शिकायतें प्राप्त हुईं, लेकिन उन्हें नामवार जानकारी देने के बजाय केवल आंकड़ों में जवाब दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के सरकारी आवासों के आसपास हुए अतिक्रमण की शिकायतों पर भी कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने सरकार से मांग की कि बेदखली वारंट वाले सभी मामलों में बिना किसी भेदभाव के तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा कि यदि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं तो प्रभावशाली लोगों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी समान कानून लागू होना चाहिए।

शिक्षा मंत्री के आदेश पर कबीरधाम में चयनात्मक कार्रवाई, छोटे कर्मचारियों को वापसी नोटिस, रसूखदार कार्यालयों में जमे शिक्षक अब भी अछूते

कवर्धा। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा 23 जून 2026 को आयोजित समीक्षा बैठक में मूल पदस्थापना से अन्यत्र संलग्न शिक्षकों एवं कर्मचारियों को तत्काल वापस भेजने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम ने 7 जुलाई 2026 को पत्र क्रमांक 4713/स्थ1.02/संलग्नीकरण/कार्यमुक्त/2026 जारी कर संबंधित अधिकारियों को संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए। बावजूद इसके जिले में अब तक मंत्री के निर्देशों का पूर्ण पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार सभी कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन एईबीएएस प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी तथा मूल संस्था में उपस्थिति नहीं होने पर वेतन आहरण नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद जिले में कई शिक्षक एवं गैर शिक्षकीय कर्मचारी अब भी विभिन्न राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत बताए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री कार्यालय, विधायक कार्यालय, सांसद कार्यालय सहित अन्य संस्थाओं में कलेक्टर के अनुमोदन से कई शिक्षक एवं कर्मचारी वर्षों से संलग्न हैं। लेकिन इन कर्मचारियों की वापसी को लेकर अब तक कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नियम केवल निचले स्तर पर कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ही लागू हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों, प्राचार्यों तथा विद्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को मूल संस्था में लौटने के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन जिन कर्मचारियों की पदस्थापना प्रभावशाली कार्यालयों में है, उनके संबंध में प्रशासनिक सख्ती नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि शिक्षा विभाग में अब चयनात्मक कार्रवाई की चर्चा जोर पकड़ रही है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब मंत्री स्तर से स्पष्ट निर्देश जारी हो चुके हैं, तब जिला प्रशासन द्वारा अब तक व्यापक स्तर पर समीक्षा कर सभी संलग्न कर्मचारियों की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। हालांकि प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा है कि जिला प्रशासन को ऐसे सभी कर्मचारियों की जानकारी पहले से उपलब्ध है। शिक्षा विभाग के जानकारों का कहना है कि यदि सरकार की मंशा वास्तव में स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करना है, तो सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किए जाने चाहिए। केवल सामान्य शिक्षकों और कर्मचारियों पर कार्रवाई कर औपचारिकता निभाना तथा प्रभावशाली कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को यथावत बनाए रखना शासन के निर्देशों की भावना के विपरीत माना जा रहा है। डीईओ के पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कर्मचारी तत्काल मूल पदस्थ संस्था में कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा वेतन आहरण नहीं होने की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह सख्ती सभी पर समान रूप से लागू होगी या केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगी। कबीरधाम जिले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिक्षा मंत्री के 23 जून के निर्देश वास्तव में धरातल पर उतर पाएंगे या फिर यह आदेश भी अन्य प्रशासनिक पत्रों की तरह केवल फाइलों तक सीमित रह जाएगा। जिले के शिक्षा जगत और आम लोगों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि प्रभावशाली कार्यालयों में वर्षों से जमे शिक्षक एवं कर्मचारी कब अपने मूल पदस्थापना स्थल पर लौटते हैं। फिलहाल, 23 जून की समीक्षा बैठक और 7 जुलाई को जारी जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद भी जिले में संलग्नीकरण समाप्त करने की प्रक्रिया अधूरी नजर आ रही है, जिससे शासन की मंशा और प्रशासनिक इच्छाशक्ति दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कबीरधाम में शिक्षा मंत्री के निर्देशों का वास्तविक और समान रूप से पालन हो पाता है या नहीं।

श्रीराम मंदिर, अयोध्या में कथित चढ़ावा व वित्तीय अनियमितताओं के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन

बेमेतरा। जिला मुख्यालय बेमेतरा स्थित श्रीराम मंदिर प्रांगण में जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा के तत्वावधान में श्रीराम मंदिर, अयोध्या से जुड़े कथित चढ़ावा एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र श्रीराम मंदिर से जुड़े मामलों में यदि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी जांच होना आवश्यक है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इस पूरे मामले पर जवाब देने से बच रही है और जनता के सामने तथ्य स्पष्ट नहीं किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा स्वयं को भगवान श्रीराम की सबसे बड़ी हितैषी बताती है, लेकिन यदि मंदिर से जुड़े वित्तीय मामलों पर सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पारदर्शिता के साथ सभी तथ्यों को सार्वजनिक करे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों को भी इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं के मन में किसी प्रकार का संदेह न रहे। कांग्रेसजनों ने मांग की कि पूरे प्रकरण की न्यायिक अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि किसी भी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने कहा कि भगवान श्रीराम किसी एक दल या संगठन की नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था के प्रतीक हैं और उनकी आस्था के नाम पर किसी भी प्रकार की कथित अनियमितता स्वीकार्य नहीं है। मंच संचालन मनोज शर्मा के द्वारा किया गया प्रदर्शन में मिथलेश वर्मा रश्मि मिश्रा ईश्वर वर्मा विजय बघेल शशि प्रभा गायकवाड सुशीला जोशी बालकुमारी ध्रुव राजू साहू झम्मन बघेल सुमन गोस्वामी रवि रजक लुकेश वर्मा रीता पाण्डेय शकुंतला साहू योगिता साहू जनता साहू बहल वर्मा ऋषि वर्मा अयोध्या चंद्राकर अंजोर यदु सतीश मार्कंडेय शेख शरीफ कुरैशी निलेश ठाकुर धनंजय साहू सिद्दीक खान निलेश ठाकुर मोहित वर्मा मिन्टा नामदेव प्रकश ठाकुर टोकेश्वर साहू चेतन साहू छम्मन यदु बलराम साहू प्रकाश साहू सीताराम यदु प्रताप साहू बलवंत साहू जगजीत सिंह मनीष परिहार संजय वर्मा प्रदीप परगनिहा गुरेंद्र वर्मा जयप्रकाश राज ऋतिक तिवारी शरद साहू सहदेव ऋतिक सलूजा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अंधेरे में 71 परिवार, 372 राजस्व प्रकरण लंबित, तेंदूपत्ता श्रमिकों की सुविधाओं पर भी सदन में उठे सवाल

कवर्धा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई अहम जनहित के मुद्दों को सदन में उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। वनांचल क्षेत्रों में बिजली संकट, रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया, कबीरधाम जिले के लंबित राजस्व प्रकरण तथा तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर पूछे गए सवालों पर सरकार ने विस्तृत लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। विधायक भावना बोहरा ने वनांचल एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए बताया कि तेलियापानी, बिरहुलडीह, कांदावानी, छीरपानी, रूखमीदादर, छिंदीडीह और अमनिया सहित कई गांव आज भी नियमित विद्युत सुविधा से वंचित हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा दिए गए लिखित जवाब में बताया गया कि जून 2026 की स्थिति में संबंधित 20 गांवों में से 8 गांव अब भी पारंपरिक विद्युत व्यवस्था से अविद्युतीकृत हैं। क्षेत्र के 71 परिवार पूरी तरह बिजली से वंचित हैं, जबकि 1,127 परिवार केवल सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था पर निर्भर हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सघन वन क्षेत्र होने के कारण इन गांवों को फिलहाल मुख्य विद्युत ग्रिड से जोड़ने की कोई योजना नहीं है। विधायक ने रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया एवं भूईयां पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का मुद्दा भी सदन में उठाया। इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि राज्य में स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया जारी है तथा सभी प्रकरणों को भूईयां पोर्टल पर प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रावधान किए जा रहे हैं।

मार्च 2024 से मार्च 2026 के बीच राज्य में इस संबंध में कुल 9 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनका निराकरण कर दिया गया है। कबीरधाम जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों को लेकर भी विधायक ने सरकार को घेरा। लिखित जवाब में बताया गया कि जिले में भू-राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत वर्तमान में 372 मूल एवं अपील प्रकरण लंबित हैं। प्रकरणों के लंबित रहने का मुख्य कारण पक्षकारों की अनुपस्थिति एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने में देरी बताया गया है। सरकार ने कहा कि राजस्व शिविर और ई-कोर्ट के माध्यम से इन मामलों के त्वरित निराकरण का प्रयास किया जा रहा है तथा इनके निपटारे के लिए 45 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा भावना बोहरा ने वन सुरक्षा समितियों, लघु वनोपज एवं तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य से जुड़े श्रमिकों और संग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं का मुद्दा भी उठाया। वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इन श्रमिकों को पारिश्रमिक के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, बीमा, सामाजिक सुरक्षा तथा उनके बच्चों को छात्रवृत्ति जैसी विभिन्न कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। विधानसभा में उठाए गए इन मुद्दों के बाद पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के वनांचल इलाकों में मूलभूत सुविधाओं, राजस्व व्यवस्था और श्रमिक कल्याण योजनाओं की स्थिति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है।

कबीरधाम को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात, अब जिले में ही बनेंगे डॉक्टर

कवर्धा। कबीरधाम जिले के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने शासकीय मेडिकल कॉलेज, कबीरधाम को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 50 एमबीबीएस सीटों के साथ संचालित करने की औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी है। इस स्वीकृति के साथ जिले की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है और अब स्थानीय विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ से संबद्ध किया गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री एवं कबीरधाम विधायक विजय शर्मा ने जिलेवासियों को बधाई देते हुए इसे कबीरधाम के विकास की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रही है और इसके लिए लगातार केंद्र एवं राज्य स्तर पर प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जिला अस्पताल का 100 बिस्तरों से बढ़ाकर 220 बिस्तरों में उन्नयन किया गया। इसके साथ ही लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण की प्रक्रिया को भी गति दी गई। कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया, जिसकी नियमित समीक्षा स्वयं उप मुख्यमंत्री करते रहे। बताया जा रहा है कि 23 जून को नई दिल्ली प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात कर इसी शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कराने का विशेष आग्रह किया था। इसके बाद लगातार फॉलोअप और समन्वय के चलते एनएमसी से स्वीकृति प्राप्त हुई। मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होने से न केवल कबीरधाम बल्कि आसपास के जिलों के लाखों लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी, आधुनिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा और गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए लोगों की बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी।

वहीं, स्थानीय युवाओं के लिए यह उपलब्धि किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। अब जिले के छात्र-छात्राओं को अपने गृह जिले में ही एमबीबीएस की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा, जिससे चिकित्सा शिक्षा अधिक सुलभ और किफायती हो सकेगी। कबीरधाम में शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना को क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह उपलब्धि आने वाले समय में कबीरधाम को प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा केंद्रों में शामिल करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

बेमेतरा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा संचालित स्टेट प्लान ऑफ एक्शन कैलेंडर 2026 के अनुसार माह जुलाई 2026 विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर माननीय अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश सरोज नन्द दास के मार्गदर्शन में व स्वर्णलता ओम यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के उपस्थिति में शासकीय हाई स्कूल मटका में 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में छात्र-छात्राओं को बताया गया कि विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत कर एवं लोगों को परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकार जैस विभिन्न जनसंख्या संबंधी मुद्दों के बारे मे जागरूक करने की जानकारी दी गई। साथ ही नालसा व सालसा द्वारा संचालित योजनाओं जैसे पॉक्सो एक्ट अधिनियम, बाल विवाह, बाल श्रम, किशोर न्याय अधिनियम, ड्रग मुक्त भारत डॉन योजना, नवीन मोटरयान अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम के संबंध में महत्पूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा से अधिकार मित्र के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र चोरभट्ठी , राशन दुकान गुबारबोड, सीमेंट दुकान गुबारबोड में विश्व जनसंख्या दिवस के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर आयोजन कर लोगो को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षकगण और प्रशिक्षण केन्द्र के ट्रेनर उपस्थित रहे । साथ ही लीगल एड डिफेंस कौंसिल के अधिवक्ता गण के द्वारा तालुका साजा में शिविर आयोजन उपस्थित लोगों जानकारी दी गई ।

सिंगारपुर स्कूल का जर्जर किचन भवन बना हादसे का इंतजार, बच्चों की सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा

सहसपुर लोहारा। जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगारपुर स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का किचन भवन इन दिनों गंभीर जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। भवन की दीवारों में गहरी दरारें पड़ गई हैं, छत कमजोर हो चुकी है और कई स्थानों से प्लास्टर झड़ रहा है। बारिश के मौसम में भवन की हालत और अधिक खराब हो गई है, जिससे कभी भी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय परिसर में स्थित यह किचन भवन मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रतिदिन यहां छात्र-छात्राओं, रसोइयों और शिक्षकों की आवाजाही रहती है। ऐसे में भवन के अचानक ढहने की स्थिति में बड़ी जनहानि हो सकती है। इसके बावजूद संबंधित विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या के समाधान के बजाय केवल आश्वासन ही मिलता रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बारिश के कारण भवन में पानी का रिसाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे उसकी मजबूती और कमजोर होती जा रही है। स्कूल परिसर में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में भी भय का माहौल बना हुआ है। पालकों का कहना है कि यदि समय रहते भवन को उपयोग से बाहर नहीं किया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की है कि तत्काल तकनीकी जांच कर जर्जर किचन भवन को असुरक्षित घोषित किया जाए तथा नए भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मध्याह्न भोजन संचालन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रदेश में लगातार स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति के कारण हादसों की खबरें सामने आती रही हैं, इसके बावजूद सिंगारपुर के इस किचन भवन को लेकर अब तक गंभीर पहल नहीं होना चिंता का विषय है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी। फिलहाल, सिंगारपुर का यह जर्जर किचन भवन प्रशासनिक उदासीनता की कहानी बयां कर रहा है और सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे।

संक्षिप्त समाचार

समय पर खाद-बीज और केसीसी मिलने से किसानों में उत्साह

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप सुकमा जिला प्रशासन ने खरीफ सीजन से ठीक पहले किसानों के लिए खाद, उन्नत बीज और ऋण की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कर प्रशासनिक तत्परता की एक अनुकरणीय मिसाल पेश की है। कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में जिले के दूरस्थ अंचलों तक कृषि सामग्रियों की सुचारू आपूर्ति की पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रशासन की इस सक्रिय, पारदर्शी और किसान-हितैषी कार्यप्रणाली से अन्नदाताओं को बिना किसी परेशानी के बोआई की तैयारी करने में मदद मिल रही है, जिससे पूरे क्षेत्र के किसानों में भारी उत्साह और आगामी फसल को लेकर एक नया विश्वास जागा है इस समयबद्ध व्यवस्था का सीधा और सुखद लाभ छिंदगढ़ विकासखंड के नयागुड़ा गांव के प्रगतिशील किसान चनासू नाग को मिला है। 8 एकड़ कृषि भूमि के मालिक चनासू नाग को कुकानार सहकारी समिति के माध्यम से न केवल आवश्यकतानुसार सब्सिडीयुक्त केसीसी ऋण उपलब्ध कराया गया, बल्कि कुकानार समिति से तत्काल एक-एक बोरी यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश और एक बोरी धान भी प्रदान किया गया। समय पर मिली इस बड़ी मदद से भावुक सोमारू ने कहा कि इससे उन पर से आर्थिक दबाव पूरी तरह हट गया और उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए इस सुचारू व्यवस्था की खुले दिल से सराहना की।एक ओर जहाँ प्रशासन किसानों को निर्बाध रूप से कृषि आदान उपलब्ध करा रहा है, वहीं दूसरी ओर अन्नदाताओं के हितों की रक्षा के लिए बिचौलियों, कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार सोसायटियों और बाजारों का औचक निरीक्षण कर कड़ी कार्रवाई कर रही हैं, जिससे किसानों को सही कीमत पर प्रमाणिक सामग्रियां मिल रही हैं। जिला प्रशासन की इस त्रिस्तरीय मुस्तैदी ऋण, खाद-बीज की आपूर्ति और सख्त निगरानी ने सुकमा के किसानों का भरोसा मजबूत कर दिया है और इस बार क्षेत्र में बंपर खरीफ उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है।

बारिश में खुले गड्ढों से बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश

रायपुर। बारिश के दौरान खुले गड्ढों और निर्माणाधीन स्थलों पर बच्चों के हादसों को गंभीरता से लेते हुए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ ने राज्य के सभी नगर निगम आयुक्तों एवं नगर पालिका परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग- ने विभिन्न स्थानों पर खुले निर्माणाधीन गड्ढों, सड़कों के गड्ढों तथा बारिश में ढकी नालियों में गिरकर बच्चों की मौत की घटनाओं पर चिंता जताई है। इसे बच्चों के जीवन के अधिकार से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए आयोग ने -बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005- की धारा 13 एवं 15 के तहत आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार सभी नगरीय निकायों को तत्काल विशेष सर्वे अभियान चलाकर खुले गड्ढों, नालियों और निर्माणाधीन स्थलों की पहचान करनी होगी। ऐसे स्थानों को या तो तत्काल भरने या उनके चारों ओर बल्ली, बैरिकेडिंग अथवा अन्य सुरक्षा घेरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बच्चों के गिरने की आशंका समाप्त हो सके। साथ ही सभी निर्माण एजेंसियों और आवासीय कॉलोनियों को निर्देशित किया गया है कि निर्माण कार्य के लिए खोदे गए नींव, कॉलम या अन्य गड्ढों के चारों ओर अनिवार्य रूप से सुरक्षा घेरा बनाया जाए। संवेदनशील निर्माण स्थलों पर चौकीदार या सुरक्षाकर्मी की तैनाती भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। संचालनालय ने यह भी कहा है कि बारिश के दौरान पानी से भरे छोटे और बड़े गड्ढों में अंतर समझ पाना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, जिससे स्कूल आते-जाते या खेलते समय दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए सभी नगरीय निकायों को इस विषय पर विशेष सतर्कता बरतने और भविष्य में होने वाले प्रत्येक निर्माण कार्य में आयोग के सुरक्षा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में मानसून पर लगा तीन दिन का ब्रेक आज होगा खत्म

रायपुर। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। लगातार बारिश के बाद बारिश ने तीन दिन का ब्रेक ले लिया है, जिससे राजधानी समेत कई जिलों में उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज से फिर बारिश के आसार जताए हैं। सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाडा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, गरयाबंद, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर में आगामी कुछ घंटों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा व बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी में शुक्रवार को सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही, लेकिन वर्षा दर्ज नहीं की गई। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह 78 और शाम को 56 प्रतिशत आर्द्रता दर्ज की गई। पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को आसमान सामान्यत: मेघमय रहेगा और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। प्रदेश में रघुनाथनगर, कुसमी और बड़ेबचेली में सर्वाधिक 50 मिमी वर्षा दर्ज की गई। सरोना में 40 मिलीमीटर तथा कोरबा, बैकुंठपुर, लैलूंगा, शंकरगढ़, मुंगेली और प्रेमनगर सहित कई क्षेत्रों में 30 मिमी बारिश हुई। बिलासपुर में 190 मिमी, पेण्ड्रारोड में 80 मिमी, अंबिकापुर में 130 मिमी और जगदलपुर में 130 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

महासमुंद पुलिस का बड़ा एक्शन: 5.160 किलो गांजा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

रायपुर। जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5.160 किलोग्राम गांजा के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में तकनीकी विश्लेषण और समन्वित कार्रवाई के जरिए उड़ीसा से गांजा सप्लायर को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जब्त गांजा की कीमत 2.58 लाख रुपये आंकी गई है, जबकि जब्त कुल संपत्ति का मूल्य 3.71 लाख रुपये है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान सूचना मिली कि मोटरसाइकिल क्रमांक ष्टत्र 11 ढ्ढक्क 1670 और स्कूटी क्रमांक ह्रष्ठ 11 स्ङ्क 2022 से उड़ीसा की ओर से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। सूचना पर सिंघोड़ा थाना क्षेत्र के एनएच-53 स्थित रेहटीखोल में नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने दोनों वाहनों को रोककर पूछताछ की। आरोपियों के जवाब संदिग्ध लगने पर तलाशी ली गई, जिसमें स्कूटी की सीट के नीचे छिपाकर रखा गया।

डबल इंजन सरकार में चिकित्सा शिक्षा का ऐतिहासिक विस्तार

छत्तीसगढ़ को मिले 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज-सीएम विष्णुदवे साय

- गीदम दंतेवाड़ा, कुनकुरी जशपुर, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा एवं कबीरधाम में 50-50 एमबीबीएस सीटों सहित कुल 250 सीटों को मिली स्वीकृति
- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा का जताया आभार

रायपुर/ संवाददाता

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से गीदम (दंतेवाड़ा), कुनकुरी (जशपुर), मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा एवं कबीरधाम में 50-50 एमबीबीएस सीटों वाले 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में एक साथ कुल 250 नई एमबीबीएस सीटों का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास का ऐतिहासिक पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसा सुदृढ़, समावेशी और आधुनिक स्वास्थ्य तंत्र विकसित करना है, जहाँ प्रदेश का कोई भी युवा डॉक्टर बनने के अपने सपने से वंचित न रहे और किसी भी नागरिक को बेहतर उपचार के लिए दूर-दराज़ के शहरों का रुख न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे गीदम (दंतेवाड़ा) से लेकर उत्तर छत्तीसगढ़ के आदिवासी वनांचल कुनकुरी (जशपुर) तक नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि डबल इंजन सरकार विकास के अवसरों को प्रदेश के अंतिम छोर तक पहुँचा रही है। यह केवल नए

संस्थानों की स्थापना नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने और दूरस्थ अंचलों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूत नींव रखने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन ला रही है। प्रदेश के दूरस्थ, आदिवासी और आकांक्षी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार आएगा। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा के प्रति समस्त छत्तीसगढ़वासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन से प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज केवल शैक्षणिक संस्थान नहीं होंगे, बल्कि चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय मानव संसाधन विकास के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित होंगे। इससे न केवल डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार होगी, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर उपचार की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी, प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई दिशा देगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाएगी।

नकटी मामले पर झूठ की राजनीति कर रहे मो. अकबर,जनता को गुमराह करने की साजिश.....

- बिल्डरों को जमीन सौंपने का आरोप सफेद झूठ, कांग्रेस अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए फैला रही भ्रम

रायपुर/ संवाददाता

वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस नेता मो. अकबर द्वारा नकटी क्षेत्र की 1076 एकड़ भूमि को बिल्डरों को सौंपने की तैयारी संबंधी आरोपों को पूरी तरह मनगढ़ंत, झूठा और राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न तथ्य हैं, न प्रमाण, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। केदार कश्यप ने कहा कि मो. अकबर पहले यह जवाब दें कि जिस भूमि से जुड़ी पूरी प्रक्रिया कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज जब साय सरकार कानून के अनुसार सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम कर रही है, तब कांग्रेस अपनी नाकामियों और पापों को छिपाने के लिए झूठे आरोपों की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि नकटी में हुई कार्रवाई किसी बिल्डर या निजी हित के लिए नहीं, बल्कि सरकारी भूमि की सुरक्षा और कानून के राज की स्थापना के लिए की गई है। साय सरकार की नीति स्पष्ट है—भू-माफिया चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे संरक्षण नहीं मिलेगा और

किसी भी गरीब के साथ अन्याय भी नहीं होने दिया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में वर्षों तक सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे पनपते रहे। अब जब उन पर वैधानिक कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस नेताओं को तकलीफ हो रही है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि कांग्रेस का उद्देश्य गरीबों का हित नहीं, बल्कि अवैध कब्जों की राजनीति को बचाना है। केदार कश्यप ने मो. अकबर को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो वे दस्तावेज और प्रमाण सार्वजनिक करें। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठ बोलने से सच नहीं बदल जाएगा। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो प्रदेश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि साय सरकार किसी भी दुष्प्रचार या राजनीतिक दबाव में आने वाली नहीं है। सरकारी भूमि की रक्षा, कानून का निष्पक्ष पालन और गरीबों के हितों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह अभियान पूरी पारदर्शिता के साथ आगे भी जारी रहेगा।

जेलों में बंदियों के पुनर्वास की दिशा में प्रभावी पहल, कौशल प्रशिक्षण से आत्मनिर्भरता की राह

- आरसेटी के माध्यम से अगरबत्ती, साबुन एवं हैंडवॉश निर्माण का प्रशिक्षण, रिहाई के बाद स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में बंदियों के पुनर्वास एवं उन्हें सम्मानजनक जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में कौशल विकास आधारित पहलें लगातार सशक्त हो रही हैं। इसी क्रम में सूरजपुर जिला जेल में सेंट्रल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) द्वारा 13 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें 35 बंदियों ने अगरबत्ती, साबुन एवं हैंडवॉश निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2 जुलाई से 13 जुलाई तक संचालित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बंदियों में उद्यमिता की भावना विकसित करना तथा रिहाई के बाद उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना था। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को उत्पाद निर्माण की तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, विपणन, वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग प्रक्रियाओं तथा विभिन्न शासकीय स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण के अंतिम दिवस सभी 35 प्रतिभागियों का लिखित एवं प्रायोगिक मूल्यांकन किया गया तथा सफल प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। जिला जेल अधीक्षक ने कहा कि इस प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और आत्मनिर्भर बनने की भावना विकसित करते हैं। वहीं आरसेटी के निदेशक ने बताया कि संस्थान केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रिहाई के बाद बैंक लिंकेज, ऋण सुविधा तथा दो वर्षों तक हैंडहोल्डिंग सहायता उपलब्ध कराकर स्वरोजगार स्थापित करने में भी सहयोग करता है। उन्होंने बताया कि अगरबत्ती एवं साबुन निर्माण जैसे लघु उद्योगों के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्ति प्रतिमाह लगभग 15 से 20 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर सकते हैं। राज्य में कौशल विकास एवं पुनर्वास आधारित ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों को नई दिशा देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर नागरिक के रूप में समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

बेटी के स्कूल प्रवेश की राह हुई आसान

सेवा सेतु केंद्र में महज 30 मिनट के अंदर मिले जरूरी प्रमाणपत्र....

- सालेपाल के राजू पोयामी ने सेवा सेतु केंद्र की त्वरित और पारदर्शी व्यवस्था की सराहना की

रायपुर/ संवाददाता

शासन द्वारा नागरिक सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से संचालित सेवा सेतु केंद्र आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहे हैं। इसका एक प्रेरक उदाहरण तब देखने को मिला, जब बस्तर जिले के तोकापाल विकासखंड के ग्राम

सालेपाल निवासी राजू पोयामी ने अपनी बेटी मनकी पोयामी के स्कूल प्रवेश के लिए आवश्यक आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनवाने हेतु सेवा सेतु केंद्र का रुख किया। राजू पोयामी ने बताया कि उनकी बेटी मनकी के स्कूल में प्रवेश के लिए इन तीनों दस्तावेजों की तत्काल आवश्यकता थी। पहले उन्हें आशंका थी कि प्रमाणपत्र बनने में कई दिन लग सकते हैं, जिससे प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। लेकिन सेवा सेतु केंद्र में आवेदन करने के बाद मात्र 30 मिनट के भीतर उन्हें आय, जाति और निवास तीनों प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दिए गए। उन्होंने कहा कि इतनी कम समय में सभी आवश्यक दस्तावेज मिल जाने से उनकी बेटी के स्कूल प्रवेश की प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सकी। राजू ने सेवा सेतु केंद्र की त्वरित, सरल और नागरिक हितैषी व्यवस्था के लिए शासन एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

13 वर्षीय छात्रा ने घर में लगाई फांसी, पुलिस जांच में जुटी

रायपुर। पाली थाना क्षेत्र के ग्राम डूमरकछार में 13 वर्षीय एक छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान भावना देवार, पिता अजय देवार, के रूप में हुई है। वह कक्षा सातवीं की छात्रा थी। जानकारी के अनुसार, छात्रा मंगलवार रात पड़ोस में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपनी छोटी बहन के साथ घर लौटी थी। देर रात उसने घर के भीतर फांसी लगा ली। घटना के समय उसके माता-पिता किसी काम से सक्ती गए हुए थे। घटना की सूचना मिलने पर पाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस आसपास के लोगों और शादी समारोह में शामिल लोगों से पूछताछ कर रही है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रकरणों की वापसी को लेकर बस्तर के युवाओं से की मुलाकात

किसकोड़ो में पहली बार वास्तविक आजादी का अनुभव कर रहे हैं-शर्मा

- नक्सल मामलों में निरुद्ध लोगों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए शासन प्रतिबद्ध
- जनहानि रहित मामलों की होगी साप्ताहिक समीक्षा, लंबित न्यायालयीन मामलों में भी तेज होगी प्रक्रिया

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल मामलों में जेल में बंद ऐसे लोगों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण और रिहाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिनके खिलाफ कोई गंभीर जनहानि का मामला दर्ज नहीं है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज बस्तर क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों, नक्सल प्रकरणों में निरुद्ध लोगों के परिजनों, नक्सल पीड़ितों तथा युवाओं से आज विधानसभा में मुलाकात कर नक्सल प्रकरणों के निराकरण और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध लोगों के प्रकरणों की शीघ्र और न्यायसंगत समीक्षा और सभी की जल्द रिहाई के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है तथा प्रत्येक पात्र मामले में विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई को मंत्रालय में गृह विभाग के प्रमुख सचिव, संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर संभाग के सभी 12 जिलों के संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित कर नक्सल प्रकरणों के निराकरण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है। बैठक में सभी लंबित प्रकरणों को दो श्रेणियों में विभाजित कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एक जिनमें जनहानि हुई हैं तथा दूसरे वे प्रकरण जिनमें जनहानि नहीं हुई है।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि जिन मामलों में जनहानि नहीं हुई है, उनकी समीक्षा संबंधित जिलों पुलिस अधीक्षक प्रत्येक सप्ताह अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं की टीम के साथ करेंगे, ताकि ऐसे मामलों का शीघ्र निराकरण कर पात्र लोगों को राहत मिल सके। इसके लिए अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं की टीम बनाई गई है। वहीं जिन मामलों में जनहानि हुई है और न्यायालय में प्रकरण लंबित हैं, उनमें चालान प्रस्तुत करने, गवाही की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा न्यायालयीन प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिन प्रकरणों में गंभीर धाराएं लगी हैं उनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि यदि किसी अभियुक्त के परिजन अपने प्रकरण की समीक्षा कराना चाहते हैं तो वे संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे सकते हैं। ऐसे आवेदनों का अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं की टीम द्वारा विधिसम्मत परीक्षण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादी हिंसा ने बस्तर सहित अनेक क्षेत्रों को वर्षों तक प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब इन क्षेत्रों में सामान्य आवाजाही भी कठिन थी, लेकिन आज स्थिति तेजी से बदल रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अत्यंत नक्सल प्रभावित रहे किसकोड़ो गांव के दौरे के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि वे अब पहली बार वास्तविक आजादी का अनुभव कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि कबीरधाम क्षेत्र में भी माओवादी गतिविधियों का प्रभाव रहा है और उन्होंने स्वयं उस दौर को निकट से देखा है। इस दौरान युवाओं ने अपनी व्यथाओं को भी उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिसपर उप मुख्यमंत्री ने सभी के समाधान का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बस्तर में शांति, विकास और विश्वास का वातावरण मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बस्तर के युवाओं से विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का आह्वान करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील की।

संपादकीय

संघर्ष की विरासत, प्रतिरोध के बीच गूंजती पंडवानी की आवाज

विपरीत हालात के बावजूद तीजन बाई ने अपनी कला को नहीं छोड़ा और उसके तहत वे महाभारत कथा की अलग-अलग बारीकियों के साथ उसके अभिनय पक्ष पर काम करती रहीं।कला जगत में ऐसे कम लोग हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में लगभग हर स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद न केवल मजबूत उपस्थिति दर्ज की, बल्कि अपनी चुनी हुई विधा को एक नया आयाम दिया।तीजन बाई और पंडवानी आज एक-दूसरे के मजबूत पर्याय के तौर पर जाने जाते हैं, तो इसकी एक ठोस पृष्ठभूमि भी है। महज नौ साल की उम्र में जब तीजन बाई ने अपने चचेरे नाना से पंडवानी का प्रशिक्षण लेना शुरू किया, तो उस उम्र में भी उन्हें समाज से लेकर अपने परिवार तक का काफी विरोध झेलना पड़ा।दरअसल, पंडवानी विधा में गायन को आमतौर पर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। आगे उनका निजी जीवन भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ और उनकी शादी भी टूटी। मगर पंडवानी और तीजन बाई ने शायद एक-दूसरे को चुन लिया था और यही वजह थी कि कमजोर सामाजिक तबके से आने और तमाम विपरीत हालात के बावजूद उन्होंने अपनी कला को नहीं छोड़ा और उसके तहत वे महाभारत कथा की अलग-अलग बारीकियों के साथ उसके अभिनय पक्ष पर काम करती रहीं।अपनी प्रतिबद्धता की वजह से ही वे न केवल अपने आसपास के गांवों में एक कामयाब पंडवानी गायिका के रूप में जानी गईं, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने भी उन्हें अपनी प्रस्तुति देने का अवसर मिला।उनकी प्रतिभा के लिए उन्हें पद्म पुरस्कारों सहित कई अन्य सम्मान से नवाजा गया, लेकिन उनकी अहमियत उनके व्यक्तित्व में मौजूद उन खासियतों से कायम रही, जिन्हें उन्होंने काफी मेहनत और संघर्ष से अर्जित किया था।उनकी प्रस्तुतियों में उत्साह, ऊर्जा, आक्रामकता, कठोरता से लेकर कोमलता और वात्सल्य के भाव दर्शकों के भीतर उतर जाते थे और इससे पता चलता है कि उन्हें इसके लिए किस स्तर की साधना से गुजरना पड़ा होगा।औपचारिक शिक्षा नहीं के बराबर होने के बावजूद अपनी चुनी हुई कला में उन्होंने जिस स्तर की बारीकियां हासिल कीं, वैसा विरले दिखता है।मौजूदा दौर में मंचीय प्रस्तुतियां महज चकाचौंध और आधुनिक तकनीक की गूंज में दबी लगती हैं, लेकिन कला और उसकी अहमियत को समझने वालों को तीजन बाई की प्रस्तुतियों के बीच ठहराव के साथ मौन की संवेदना के मायने भीतर तक उतर जाना ज्यादा याद रह जाता है।

दुनिया के कई देशों ने इस समस्या को सार्वजनिक नीति का विषय बनाया है। ब्रिटेन ने अकेलेपन से निपटने के लिए विशेष रणनीति तैयार की थी और जापान ने भी सामाजिक अलगाव की बढ़ती समस्या को देखते हुए अलग सरकारी व्यवस्था बनाई। भारत में भी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को लेकर चर्चा बढ़ी है, लेकिन अभी इस दिशा में व्यापक सामाजिक पहल की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, सामुदायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बुजुर्गों के लिए सामाजिक मंच विकसित करने की जरूरत है, लेकिन समाधान केवल सरकारी योजनाओं से नहीं निकलेगा। समाज को भी अपने भीतर झांकना होगा। पड़ोस, मित्रता, सामुदायिक गतिविधियां, पुस्तकालय, उद्यान, वरिष्ठ नागरिक समूह और परिवार के भीतर संवाद—ये सभी सामाजिक जीवन के वे सूत्र हैं, जो व्यक्ति को अकेलेपन से बचाते हैं। आज जरूरत यह है कि हम डिजिटल संपर्क और मानवीय संबंधों के बीच का अंतर समझें। संबंध केवल संपर्क करने से नहीं बनते, उन्हें समय, संवाद और संवेदना से निभाया जाता है।

स्क्रीन के इस पार भीड़, उस पार अकेला इंसान, सिकुड़ रही हैं हमारी संवेदनाएं

(श्याम यादव)

मोबाइल स्क्रीन में व्यस्त लोगों की भीड़ के बीच अकेला खड़ा एक व्यक्ति, जो डिजिटल युग में बढ़ते अकेलेपन और मानवीय संबंधों की घटती आत्मीयता का प्रतीक है।डिजिटल दुनिया में पहले से कहीं अधिक जुड़े होने के बावजूद लोग भावनात्मक रूप से पहले से अधिक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मौजूदा दौर में दुनिया की भीड़ ही सबसे ज्यादा चर्चा और चिंता का कारण बन रही है। हमारे आसपास इतने लोग दिखाई देते हैं कि कई बार हम खुद को गुम होता पाते हैं। यह प्रत्यक्ष दुनिया की बात है, लेकिन इसके अलावा आज हम अकेले में भी कभी अकेले नहीं होते हैं। यानी वास्तविक दुनिया की व्यस्तताओं से इतर आभासी दुनिया में हमारी उपस्थिति हमें जरूरत से ज्यादा बड़ी भीड़ से घेरे रखती है।

इसके बावजूद आखिर ऐसा क्या है और क्यों है कि चारों तरफ लोगों और भीड़ से घिरे होने के बावजूद हम अक्सर खुद को अकेला पाते हैं, अकेलेपन को लेकर परेशान होते हैं। यही शायद आज हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। मनुष्य पहले कभी इतना जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन शायद पहले कभी इतना अकेला भी नहीं था। मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया और डिजिटल संपर्कों के इस दौर में संवाद बढ़ा है, पर आत्मीयता घटी है। यही कारण है कि अकेलापन अब केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन गया है।

यों तो आभासी दुनिया में हर वक्त भीड़ देखने या उसके बीच मौजूद होने के बावजूद अकेलेपन के एहसास को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है, लेकिन कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की सामाजिक संपर्क आयोग की रिपोर्ट ने भी अकेलेपन को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बताया है। दुनिया भर में हर वर्ष आठ लाख से ज्यादा लोगों की मौत सामाजिक अलगाव और अकेलेपन से जुड़ी हुई मानी जाती है। इससे पता चलता है कि अकेलापन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न भी है।

भारत में परिवार केवल आर्थिक संस्था की हैसियत में चलने वाला कोई ढांचा नहीं है, बल्कि भावनात्मक सहारे का आधार भी रहे हैं। संयुक्त परिवारों में तो कई पीढ़ियां साथ रहती थीं। घरों में बातचीत, हंसी, तकरार और अपनापन जीवन का हिस्सा थे। आज शहरीकरण और बदलती जीवनशैली ने परिवारों को छोटी-छोटी इकाइयों में बांट दिया है। लोग एक ही घर में रहते हुए भी अलग-अलग कमरों और उनमें भी अलग-अलग 'स्क्रीन' में सिमट गए हैं। यह शहरों की तस्वीर है, लेकिन सच यह है कि ग्रामीण समाज भी इस बदलाव से अछूता नहीं है। रोजगार और शिक्षा की तलाश में युवा शहरों की ओर चले गए हैं। गांवों में पीछे छूटे माता-पिता और बुजुर्ग अक्सर सामाजिक और भावनात्मक अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। वहीं शहरों में रहने वाला युवा वर्ग भी प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा और व्यावसायिक दबावों के बीच अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता है।

सच यह है कि अकेलापन उम्र नहीं देखता। बुजुर्गों के साथ-साथ युवा और किशोर भी इसकी चपेट में हैं। पढ़ाई, करिअर, असफलता का भय, रिश्तों की अस्थिरता और बढ़ती महत्त्वाकांक्षाएं व्यक्ति को भीतर से थका रही हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर संवाद का एक गहरा अभाव पैदा हो गया है। सोशल मीडिया ने संपर्क के नए अवसर दिए हैं, लेकिन कई बार उसने निकटता का भ्रम भी पैदा किया है। मित्रता 'फॉलोअर' और 'लाइक' में बदलती और सिमटती जा रही है। हजारों संपर्कों के बावजूद लोग अपनी समस्याएं और भावनाएं साझा करने वाला कोई करीबी व्यक्ति नहीं खोज पाते। लोग 'ऑनलाइन' हैं, पर एक-दूसरे के जीवन में उपस्थित नहीं हैं। तकनीक ने संचार को सरल बनाया है, लेकिन मानवीय संबंधों का विकल्प अभी तक नहीं बन सकी है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक अकेलापन, अवसाद, चिंता, नींद की समस्या, हृदय रोग और समयपूर्व मृत्यु के जोखिम को बढ़ा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सामाजिक संबंधों को अब स्वास्थ्य के एक महत्त्वपूर्ण आधार के रूप में देखने की जरूरत पर बल दिया है। यह एक ऐसी अदृश्य महामारी है, जो धीरे-धीरे समाज की जड़ों को प्रभावित कर रही है।

दुनिया के कई देशों ने इस समस्या को सार्वजनिक नीति का विषय बनाया है। ब्रिटेन ने अकेलेपन से निपटने के लिए विशेष रणनीति तैयार की थी और जापान ने भी सामाजिक अलगाव की बढ़ती समस्या को देखते हुए अलग सरकारी व्यवस्था बनाई। भारत में भी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को लेकर चर्चा बढ़ी है, लेकिन अभी इस दिशा में व्यापक सामाजिक पहल की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, सामुदायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बुजुर्गों के लिए सामाजिक मंच विकसित करने की जरूरत है, लेकिन समाधान केवल सरकारी योजनाओं से नहीं निकलेगा। समाज को भी अपने भीतर झांकना होगा। पड़ोस, मित्रता, सामुदायिक गतिविधियां, पुस्तकालय, उद्यान, वरिष्ठ नागरिक समूह और परिवार के भीतर संवाद—ये सभी सामाजिक जीवन के वे सूत्र हैं, जो व्यक्ति को अकेलेपन से बचाते हैं।

आज जरूरत यह है कि हम डिजिटल संपर्क और मानवीय संबंधों के बीच का अंतर समझें। संबंध केवल संपर्क करने से नहीं बनते, उन्हें समय, संवाद और संवेदना से निभाया जाता है। किसी का हाल पूछ लेना, किसी बुजुर्ग के साथ कुछ समय बैठ जाना या किसी मित्र की चुप्पी को सुन लेना भी सामाजिक उपचार का काम कर सकता है। भारत जैसे भावनात्मक समाज की सबसे बड़ी ताकत उसके रिश्ते, पड़ोस, साझा जीवन और संवाद की परंपरा रही है। अगर ये कमजोर पड़ते हैं, तो अकेलापन केवल व्यक्ति की समस्या नहीं रहता, वह समाज की भी समस्या बन जाता है। डिजिटल युग में तकनीक आवश्यक है, लेकिन वह मानवीय संबंधों का विकल्प नहीं हो सकती, क्योंकि आखिरकार मनुष्य को वस्तुओं से अधिक किसी अपने के होने की आवश्यकता होती है।

समंदर बन गई हैं महानगरों की सड़कें, डूबती गाड़ियों को कोई किनारा नहीं मिलता

(नीरज कुमार दुबे)

क्या हम 2047 के विकसित भारत की इमारत उस बुनियाद पर खड़ी कर रहे हैं जो हर मानसून में हिल जाती है? क्या अब समय नहीं आ गया है कि विकास के दावों से पहले शहरों की जल निकासी व्यवस्था, निर्माण की गुणवत्ता, नगर नियोजन और प्रशासनिक जवाबदेही को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाए?

हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे हैं। हम आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट शहरों और वैश्विक स्तर की सुविधाओं का दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या हर मॉनसून हमारे इन सभी दावों की वास्तविकता सामने नहीं रख देता? क्या यह सवाल पूछने का समय नहीं आ गया है कि यदि हमारे महानगर और राज्य की राजधानियां कुछ घंटों की बारिश भी नहीं झेल पा रही हैं, तो विकसित भारत की बुनियाद आखिर कितनी मजबूत है?

क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और गुरुग्राम जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र हर वर्ष मानसून आते ही जलभराव, जाम और अव्यवस्था की पहचान बन जाते हैं? क्या यह केवल मौसम की मार है, या फिर हमारी नगर योजना, निर्माण व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारी की सबसे बड़ी असफलता है? यदि हर वर्ष यही स्थिति बननी है, तो फिर हर वर्ष होने वाली तैयारियों और बैठकों का परिणाम आखिर कहां दिखाई देता है?

क्या स्मार्ट सिटी का अर्थ केवल चौड़ी सड़कें, चमकदार भवन और आकर्षक परियोजनाएं हैं? क्या स्मार्ट शहर वह नहीं होना चाहिए जो सामान्य से अधिक बारिश को भी सहजता से संभाल सके? यदि अरबों रुपये जल निकासी, सड़क निर्माण और शहरी विकास पर खर्च हो रहे हैं, तो पहली तेज बारिश में ही सड़कें नदी और चौराहे तालाब क्यों बन जाते हैं?

क्या हर मानसून के बाद वही तस्वीरें, वही बयान और वही आश्वासन सुनना हमारी नियति बन चुकी है? क्या कभी किसी अधिकारी, किसी एजेंसी या किसी निर्माण करने वाली संस्था की जवाबदेही तय हुई? क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं कि हर वर्ष खर्च होने वाला धन आखिर किस काम में लगाया जाता है?

क्या समस्या केवल अधिक बारिश की है, या फिर प्राकृतिक जलमार्गों पर अतिक्रमण, बिना योजना के विस्तार, कमजोर निर्माण और रखरखाव की अनदेखी इसकी असली वजह है? क्या नदियों, तालाबों और पुराने जल निकासी मार्गों को पाटकर खड़ी की गई इमारतों की कीमत अब पूरा समाज नहीं चुका रहा है? यदि शहरों की सांस लेने वाली प्राकृतिक व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाएगा, तो पानी आखिर जाएगा कहां?

क्या यह सामान्य बात मानी जा सकती है कि बारिश होते ही एंबुलेंस फंस जाए, बच्चे स्कूल न पहुंच सकें, कर्मचारी दफ्तर न जा सकें, बाजार ठप हो जाएं, रेल और हवाई यात्रा थम जाएं और सामान्य जीवन रुक जाए? क्या हर वर्ष होने वाले आर्थिक नुकसान, समय की बर्बादी और जनजीवन की परेशानी का कोई हिसाब भी रखा जाता है? यदि रखा जाता है, तो फिर समाधान आज तक क्यों नहीं मिला?

क्या विकसित भारत केवल बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस वे और गगनचुंबी इमारतों से बनेगा? या फिर उसकी पहचान ऐसी मजबूत बुनियादी व्यवस्था से होगी जो हर मौसम में नागरिकों को सुरक्षित और सुगम जीवन दे सके? क्या विश्व स्तर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना उन शहरों के सहारे पूरा होगा जो हर मानसून में ठहर जाते हैं?

क्या केवल सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाना पर्याप्त है? क्या नागरिकों की भी जिम्मेदारी नहीं कि वे नालों में कचरा न डालें, जलमार्गों पर अतिक्रमण का विरोध करें और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं? लेकिन क्या यह भी उतना ही सच नहीं कि व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी पर होती है जिसके हाथ में योजना, संसाधन और निर्णय की शक्ति होती है? देखा जाये तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम 2047 के विकसित भारत की इमारत उस बुनियाद पर खड़ी कर रहे हैं जो हर मानसून में हिल जाती है? क्या अब समय नहीं आ गया है कि विकास के दावों से पहले शहरों की जल निकासी व्यवस्था, निर्माण की गुणवत्ता, नगर नियोजन और प्रशासनिक जवाबदेही को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाए? क्या जनता को हर वर्ष एक ही परेशानी झेलने के लिए मजबूर रखना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान हो सकती है? और यदि इन सवालों का उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है, तो फिर क्या हमें पहले विकसित भारत का सपना देखना चाहिए, या पहले उसकी मजबूत बुनियाद तैयार करनी चाहिए?(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

'जलालाबाद' से 'परशुरामपुरी' बनने की गौरवगाथा में सांस्कृतिक और आर्थिक पुनरुत्थान

प्राचीन, सनातन और वास्तविक गौरव परशुरामपुरी का यह नाम परिवर्तन वास्तविकता में केवल धार्मिक नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा आर्थिक गेम-चेंजर साबित होने जा रहा है। जैसे ही यह क्षेत्र आधिकारिक तौर पर परशुरामपुरी के रूप में स्थापित होगा, देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल, लॉज, परिवहन, हस्तशिल्प, और पूजा-सामग्री से जुड़े स्थानीय व्यापार को भारी गति मिलेगी। युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

(रुद्र प्रताप दुबे)

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर 'परशुरामपुरी' करके सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में अहम कदम उठाया है, जिससे भगवान परशुराम की जन्मस्थली को वैश्विक पहचान मिलने के साथ ही धार्मिक पर्यटन से क्षेत्र के आर्थिक विकास की नींव रखी गई है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 6 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर 'परशुरामपुरी' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मुगल कालीन नाम को हटाकर अपनी मूल सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटना, मात्र एक नाम का परिवर्तन नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली अतीत और सनातन अस्मिता की पुनर्स्थापना है। जलालाबाद से परशुराम पुरी की यह यात्रा केवल एक कस्बे के नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं है। यह उस सोच का विस्तार है जिसमें स्थानीय इतिहास, लोक-आस्था और सांस्कृतिक स्मृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान परशुराम, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों के प्रतीक माने जाते हैं, उनकी जन्मस्थली को उचित पहचान मिलना नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का माध्यम बन सकता है।

जलालाबाद का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान परशुराम की तपोभूमि और जन्मस्थली रहा है। इसके बाद, महाभारत काल में भी इस क्षेत्र का विशेष महत्व था, माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ के वनों में बिताया था लेकिन मुगल काल में थोपे गए इस नाम के कारण इस भूमि की वास्तविक पहचान कहीं छिप गई थी। मुगल दस्तावेज़ों

में भी इस क्षेत्र का जिक्र एक महत्वपूर्ण परगने के रूप में करके इसकी महत्वपूर्ण धार्मिक पहचान को मिटाने का काम किया गया।

प्राचीन, सनातन और वास्तविक गौरव परशुरामपुरी का यह नाम परिवर्तन वास्तविकता में केवल धार्मिक नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा आर्थिक गेम-चेंजर साबित होने जा रहा है। जैसे ही यह क्षेत्र आधिकारिक तौर पर परशुरामपुरी के रूप में स्थापित होगा, देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल, लॉज, परिवहन, हस्तशिल्प, और पूजा-सामग्री से जुड़े स्थानीय व्यापार को भारी गति मिलेगी। युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। परशुरामपुरी के भव्य विकास के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, मंदिर परिसर का सुंदरीकरण और बुनियादी ढांचागत विकास तेज होगा, जिससे इस पूरे क्षेत्र के आर्थिक स्तर में भारी सुधार देखने को मिलेगा। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक केंद्रों में हाल के वर्षों में हुए कायाकल्प के बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या और स्थानीय आय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है—परशुरामपुरी से भी वैसी ही अपेक्षा की जा रही है।वर्तमान में केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद जब उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे तब बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने परशुराम मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, सड़क संपर्क, बिजली-पानी की बेहतर व्यवस्था और श्रद्धालु सुविधा केंद्रों पर निवेश करना प्रारंभ कर दिया था। अब शाहजहांपुर से सटे जिलों के लोगों का मानना है कि यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में एक प्रमुख धार्मिक-पर्यटन गंतव्य के रूप में उभर सकता है। शाहजहांपुर, जो अब तक मुख्यतः कृषि और लघु उद्योगों पर निर्भर रहा है, मात्र इस पहचान के जरिए ही धार्मिक अर्थव्यवस्था के मानचित्र पर भी अपनी जगह बना सकता है।

जलालाबाद को परशुरामपुरी बनाने का यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस वृहद् सोच का हिस्सा है, जो भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को राष्ट्र के विकास का आधार मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि भगवान परशुराम केवल एक जाति या वर्ग के आराध्य नहीं, बल्कि पूरे भारत के न्याय, करुणा और पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने कई अवसरों पर रेखांकित किया है कि भारत की प्राचीन अस्मिता और महापुरुषों के गौरव को पुनर्स्थापित करना ही अमृत काल का मुख्य संकल्प है। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 'विकास भी और विरासत भी की सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यह रेखांकित करते रहे हैं कि उनकी सरकार विकास के साथ-साथ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक पहचान को भी मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते वर्षों में इलाहाबाद से प्रयागराज, मुगलसराय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जैसे कई नामकरणों के जरिए यह नीति लगातार आगे बढ़ी है। इस ऐतिहासिक निर्णय को धरातल पर उतारने का श्रेय केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के साथ ही शाहजहांपुर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनथक प्रयासों को जाता है। स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों के एकजुट नेतृत्व और भगीरथ प्रयास का ही परिणाम है कि शासन-प्रशासन स्तर की सभी कड़ियों को पार करते हुए इस प्रस्ताव को कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिल सकी। जनप्रतिनिधियों की इस सजगता ने क्षेत्र के लोगों को अपनी जड़ों पर गर्व करने का ऐतिहासिक अवसर देते हुए इस ऐतिहासिक क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने का रास्ता खोल दिया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के दिव्य स्वरूप के बाद, अब परशुरामपुरी का यह कायाकल्प सनातन संस्कृति के ध्वज को और ऊँचा ले जाएगा।स्थानीय जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करके सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक विकास के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोना ही नव्य उत्तर प्रदेश का असली मंत्र है।

नक्सल मामलों में निरुद्ध लोगों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए शासन प्रतिबद्ध : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रकरणों की वापसी को लेकर बस्तर के युवाओं से की मुलाकात

जनहानि रहित मामलों की होगी साप्ताहिक समीक्षा, लंबित न्यायालयीन मामलों में भी तेज होगी प्रक्रिया

बस्तर। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल मामलों में जेल में बंद ऐसे लोगों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण और रिहाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिनके खिलाफ कोई गंभीर जनहानि का मामला दर्ज नहीं है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों, नक्सल प्रकरणों में निरुद्ध लोगों के परिजनों, नक्सल पीड़ितों तथा युवाओं से आज विधानसभा में मुलाकात कर नक्सल प्रकरणों के निराकरण और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध लोगों के प्रकरणों की शीघ्र और न्यायसंगत समीक्षा और सभी की जल्द रिहाई के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है तथा प्रत्येक पात्र मामले में विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई को मंत्रालय में गृह विभाग के प्रमुख सचिव, संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर संभाग के सभी 12 जिलों के संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित कर नक्सल प्रकरणों के निराकरण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है। बैठक में सभी लंबित प्रकरणों को दो श्रेणियों में विभाजित कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

एक जिनमें जनहानि हुई हैं तथा दूसरे वे प्रकरण जिनमें जनहानि नहीं हुई है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि जिन मामलों में जनहानि नहीं हुई है, उनकी समीक्षा संबंधित जिलों पुलिस अधीक्षक प्रत्येक सप्ताह अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं की टीम के साथ करेंगे, ताकि ऐसे मामलों का शीघ्र निराकरण कर पात्र लोगों को राहत मिल सके। इसके लिए अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं की टीम बनाई गई है। वहीं जिन मामलों में जनहानि हुई है और न्यायालय में प्रकरण लंबित हैं, उनमें चालान प्रस्तुत करने, गवाही की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा न्यायालयीन प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिन प्रकरणों में गंभीर धाराएं लगी हैं उनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। शर्मा ने कहा कि यदि किसी अभियुक्त के परिजन अपने प्रकरण की समीक्षा कराना चाहते हैं तो वे संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे सकते हैं। ऐसे आवेदनों का अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं की टीम द्वारा विधिसम्मत परीक्षण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादी हिंसा ने बस्तर सहित अनेक क्षेत्रों को वर्षों तक प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब इन क्षेत्रों में सामान्य आवाजाही भी कठिन थी, लेकिन आज स्थिति तेजी से बदल रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अत्यंत नक्सल प्रभावित रहे किसकोड़ो गांव के दौरे के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि वे अब पहली बार वास्तविक आजादी का अनुभव कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि कबीरधाम क्षेत्र में भी माओवादी गतिविधियों का प्रभाव रहा है और उन्होंने स्वयं उस दौर को निकट से देखा है। इस दौरान युवाओं ने अपनी व्यथाओं को भी उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिसपर उप मुख्यमंत्री ने सभी के समाधान का आश्वासन दिया। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बस्तर में शांति, विकास और विश्वास का वातावरण मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है।

उन्होंने बस्तर के युवाओं से विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का आह्वान करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचते हुए प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने का आग्रह किया तथा कहा कि बस्तर के जैविक उत्पादों को एनपीओपी के तहत प्रमाणित कर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है।

सफलता की कहानी : अबुझमाड़ के दूरस्थ गांवों में सौर ऊर्जा से पहुंचा स्वच्छ पेयजल, बदली ग्रामीणों की जिंदगी

नारायणपुर। नारायणपुर के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में क्रेडा की पहल ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। जिले के अनेक गांवों और पाराटोलों में सोलर ड्यूल पंप स्थापित कर स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जिससे वर्षों पुरानी जल संकट की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। ग्राम नेलांगुर, पदमकोट, जाटलूर, उसेबेड़ा, हरबेल, कस्तुरमेंटा-2, घुरबेड़ा और गुमरका सहित कई दूरस्थ गांवों में लगाए गए सोलर ड्यूल पंपों से अब ग्रामीणों को गांव में ही स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है। पहले लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और कई स्थानों पर झिरिया का दूषित पानी पीने की मजबूरी थी, जिससे जलजनित बीमारियों का खतरा बना रहता था। क्रेडा द्वारा शुरू की गई इस पहल से ग्रामीणों को न केवल शुद्ध पेयजल मिल रहा है, बल्कि उनका समय और श्रम भी बच रहा है। महिलाओं और बच्चों को अब पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ता, जिससे वे अपने अन्य आवश्यक कार्यों और शिक्षा पर अधिक समय दे पा रहे हैं। जिले के 371 ग्रामों एवं पाराटोलों में सोलर ड्यूल पंप स्थापना का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 1,064 सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिनमें से 849 पंपों की स्थापना पूरी की जा चुकी है। शेष स्थानों पर भी तेजी से कार्य जारी है।सौर ऊर्जा आधारित यह व्यवस्था पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ बिजली पर निर्भरता भी कम करती है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी बिना किसी बाधा के पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सोलर ड्यूल पंप लगने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अब उन्हें स्वच्छ पानी आसानी से मिल रहा है, जिससे परिवारों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और जल संकट की चिंता काफी कम हो गई है। यह पहल ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा और सतत ऊर्जा के समन्वय का एक प्रभावी उदाहरण बनकर उभर रही है।

पोटगांव के मंदिर परिसर में कथित अवैध निर्माण का मामला गरमाया, ग्रामीणों ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की लगाई गुहार

कांकेर। कांकेर जिला के कोरर पोटगांव के मंदिर परिसर में कथित अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। आवेदन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पूर्व में दिए गए आवेदन पर राजस्व विभाग द्वारा जांच के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जांच प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि 30 जून को स्थल निरीक्षण की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में आगे बढ़ाया गया। 5 जुलाई को तहसीलदार, नायब तहसीलदार और आरआई मौके पर पहुंचे, लेकिन आवेदनकर्ताओं का आरोप है कि बिना सभी पक्षों की बात सुने और पर्याप्त जांच किए कार्रवाई पूरी कर दी गई। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव में वास्तविक तथ्यों को शामिल नहीं किया गया तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर भी नहीं मिला। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक मंदिर परिसर के आसपास कथित रूप से नियमों के विपरीत निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने संबंधित निर्माण कार्य को तत्काल रोकने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि मामले की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से कराई जाए ताकि मंदिर परिसर से जुड़े विवाद का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निराकरण हो सके।

मद्देड में सात दिन तक शिवमय रहा माहौल, चंद्र मौलेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न

बीजापुर। उसूर ब्लॉक के मद्देड में नव-निर्मित चंद्र मौलेश्वर महादेव मंदिर सात दिनों तक शिवभक्ति का प्रमुख केंद्र बना रहा। 5 से 11 जुलाई तक आयोजित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शनिवार को वैदिक रीति-रिवाजों के साथ समापन हुआ। अंतिम दिन हवन की पूर्णाहुति के बाद श्रद्धालुओं ने नव-स्थापित भगवान चंद्र मौलेश्वर महादेव के दर्शन कर परिवार और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की।महोत्सव के दौरान प्रतिदिन रुद्राभिषेक, हवन, पूजन, भजन-कीर्तन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। आयोजन में बिलासपुर, उज्जैन, रीवा और कर्नाटक से पहुंचे 11 विद्वान आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार और शास्त्रोक्त विधि से भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा कराई। सात दिनों तक चले धार्मिक अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।आयोजन में कंदकोरी श्रीनू एवं प्रभा, दिनेश सोनी एवं कुसमा सोनी तथा हेमंत तिवारी एवं कृष्णा तिवारी यजमान के रूप में शामिल रहे और सभी प्रमुख अनुष्ठानों में सहभागिता निभाई। महोत्सव के दौरान 10 जुलाई को विशाल महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महिलाओं और कन्याओं ने पारंपरिक वेशभूषा में कलश यात्रा निकाली। पूरे मद्देड में ÷हर-हर महादेव÷ और ÷बम-बम भोले÷ के जयघोष गूंजते रहे, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया। धार्मिक आयोजन में बीजापुर, जगदलपुर और रायपुर के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र से भी श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए सातों दिन लोगों की भीड़ लगी रही। आयोजन की व्यवस्थाओं में करनम श्रीनिवास, एम. मिथलेश, हेमंत तिवारी, मंचरला शैलेष, के. धनंजय, आशीष भट्टड़, राहुल, एल्लन धनंजय, पी. सचिन, बी. सचिन, प्रसाद सहित अनेक युवाओं ने सेवा दी। वहीं एम. ज्योति, लवण्या और अन्य महिलाओं ने कलश यात्रा, प्रसाद वितरण तथा पूजा व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। श्रद्धालुओं का कहना है कि नव-निर्मित चंद्र मौलेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा और भविष्य में यहां दूर-दराज से श्रद्धालुओं का आगमन बढ़ेगा।

पुनर्वास केंद्र पहुंचकर खाद्य विभाग ने किया राशन कार्डों का ई-केवाईसी

बीजापुर। पुनर्वासित (विस्थापित या स्थानांतरित) परिवारों को खाद्य सुरक्षा का निर्बाध लाभ सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें आधार-सीडेड राशन कार्ड (आधार और ई-केवाईसी अपडेटेड) के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाता है। इसके तहत उन्हें हर महीने पात्र श्रेणी के अनुसार 5 किलो से 35 किलो तक मुफ्त खाद्यान्न का अधिकार प्राप्त है। बीजापुर जिले में पुनर्वासित परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के मिले, इसके लिए जिला प्रशासन ने मैदानी स्तर पर पहल की है। कलेक्टर विश्वदीप के निर्देशन और जिला विभागीय खाद्य अधिकारी के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग की टीम ने पुनर्वास केंद्र पहुंचकर सभी पात्र हितग्राहियों के राशन कार्डों का ई-केवाईसी पूरा किया। अभियान के दौरान हितग्राहियों के जरूरी दस्तावेजों का मौके पर ही सत्यापन किया और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराई। इससे पुनर्वासित परिवारों को ई-केवाईसी के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। यह अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को नियमित राशन उपलब्ध कराने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ई-केवाईसी पूरा होने से राशन कार्ड अद्यतन रहेंगे। इससे हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से समय पर खाद्यान्न लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विभाग लोगों को समय पर ई-केवाईसी कराने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रहा है। विभाग ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हर पात्र परिवार तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कड़ी में आगे भी जिले के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

अंतर्जातीय विवाह करने वाले नवदंपती का सम्मान, कलेक्टर ने सौंपा प्रशस्ति पत्र

बीजापुर। सामाजिक समरसता और जातिगत भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से संचालित अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सोमवार को जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अंतर्जातीय विवाह करने वाले नवदंपती सचेन्द्र कुमार और प्रियंका झाड़ी का सम्मान किया गया। कलेक्टर विश्वदीप ने दोनों को प्रशस्ति पत्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके सुखद दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में कलेक्टर ने कहा कि अंतर्जातीय विवाह समाज में समानता और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम हैं। ऐसे निर्णय सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने के साथ नई पीढ़ी के लिए सकारात्मक संदेश भी देते हैं। देवेंद्र सिंह सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास ने बताया कि राज्य शासन की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य सामाजिक समरसता को मजबूत करना है। इसके तहत पात्र दंपत्तियों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता है।

धान हेराफेरी मामले में कांग्रेस का सड़क पर शक्ति प्रदर्शन, मरकाटोला में कांग्रेस का चक्का जाम, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज

3848 क्विंटल धान हेराफेरी प्रकरण में बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग, चक्का जाम के बाद मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

कांकेर। मरकाटोला लैम्पस अंतर्गत तालाकुर्री धान खरीदी केंद्र में सामने आए 3848 क्विंटल धान हेराफेरी मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। इस मामले में केवल तीन छोटे कर्मचारियों के खिलाफएफआईआर दर्ज किए जाने और कथित रूप से बड़े अधिकारियों को कार्रवाई से बाहर रखने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांकेर (ग्रामीण) के नेतृत्व में मरकाटोला में व्यापक आंदोलन किया गया। आंदोलन के तहत राज्य राजमार्ग पर निर्धारित समय तक शांतिपूर्ण चक्का जाम कर विरोध दर्ज कराया गया, जिसके कारण कुछ समय तक वाहनों का आवागमन प्रभावित रहा। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया तथा जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और सभी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं, युवा, कांग्रेस पदाधिकारी और ग्रामीण शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफजमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि इतने बड़े पैमाने पर धान की हेराफेरी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर नहीं डाली जा सकती, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की भूमिका की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

किसानों के विश्वास से खिलवाड़ का आरोप, जवाबदेही तय करने की मांग-धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बिरेश ठाकुर ने कहा कि यह मामला केवल धान की हेराफेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों के विश्वास और उनके अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो जांच केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिन अधिकारियों के स्तर पर निर्णय लिए गए और जिनकी निगरानी में पूरा खरीदी कार्य संचालित हुआ, उनकी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों ने सरकार की व्यवस्था पर भरोसा कर अपनी उपज खरीदी केंद्रों में बेची थी, लेकिन यदि उसी व्यवस्था में अनियमितता सामने आती है तो यह सीधे किसानों के हितों पर आघात है। कांग्रेस ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लीपापोती स्वीकार नहीं करेगी और अंतिम दोषी तक कार्रवाई की मांग करती रहेगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसंत यादव ने कहा कि जिला प्रशासन की निष्पक्षता तभी सिद्ध होगी जब बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल तीन कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के हितों से जुड़े इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी और दोषियों को सजा दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा।

सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा, उच्चस्तरीय जांच की मांग-प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नरेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करती है, लेकिन धरातल पर वास्तविक स्थिति इससे अलग दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि हजारों क्विंटल धान की हेराफेरी जैसी घटना बिना प्रशासनिक लापरवाही या संरक्षण के संभव नहीं हो सकती। यदि सरकार पारदर्शिता चाहती है तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि बड़े अधिकारियों के खिलाफकार्रवाई में देरी क्यों हो रही है।ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांकेर (ग्रामीण) के अध्यक्ष लोमेन्द्र यादव ने कहा कि इस पूरे मामले में छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि वास्तविक जिम्मेदार अधिकारी अब तक जांच और कार्रवाई से बाहर हैं। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कर सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए तथा विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर आंदोलन को और व्यापक रूप देगी तथा जिला कार्यालय का घेराव सहित बड़े जनआंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी। धरना-प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से 3848 क्विंटल धान हेराफेरी मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने, पूरे प्रकरण में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने, बड़े अधिकारियों की भूमिका की अलग से जांच कर उन्हें भी आरोपी बनाए जाने तथा किसानों के साथ हुए अन्याय का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने की मांग की गई।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि जांच निष्पक्ष हुई तो पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी और यह स्पष्ट होगा कि धान हेराफेरी के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस ने मांग की कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या उच्चस्तरीय समिति से कराई जाए ताकि किसानों का विश्वास दोबारा स्थापित हो सके। आंदोलन के समापन पर कांग्रेस नेताओं ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह संघर्ष किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि किसानों के सम्मान, उनके अधिकारों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जब तक पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और सभी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष बसंत यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष बिरेश ठाकुर, प्रदेश महामंत्री नरेश ठाकुर।

संक्षिप्त समाचार

गौरेला में पेंशनर्स महासंघ की बैठक, डीआर, कैशलेस इलाज और लंबित एरियर समेत प्रमुख मांगों पर सरकार से जल्द निर्णय की उम्मीद

गौरेला। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ की जिला स्तरीय बैठक सोमवार को गौरेला स्थित मिश्री देवी शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेशभर से आए संगठन के पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों ने भाग लिया। इस दौरान पेंशनरों की विभिन्न लंबित मांगों, संगठन के विस्तार और उनके हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि 10 जुलाई को मंत्रालय में मुख्य सचिव विकासशील के साथ लगभग एक घंटे तक हुई बैठक में पेंशनरों और परिवार पेंशनरों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष कई प्रमुख मांगें रखी गई हैं, जिन पर सकारात्मक चर्चा हुई है और जल्द समाधान की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि महासंघ ने 1 जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) की स्वीकृति एवं एरियर का भुगतान, राज्य के पेंशनरों को प्रस्तावित कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल करने, पेंशनर कल्याण मंडल के पुनर्गठन, पेंशनर कल्याण निधि नियमों में संशोधन, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनरों के लिए एक सहायक सहित निःशुल्क बस यात्रा, तथा 'न मांगक्क्न जांच प्रमाणपत्र' के नाम पर पेंशन रोके जाने की प्रवृत्ति समाप्त करने जैसी प्रमुख मांगें सरकार के समक्ष रखी हैं। बैठक में यह मांग भी उठाई गई कि सभी संभागों एवं जिलों में अलग पेंशन कार्यालय स्थापित किए जाएं, सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी वैध देयकों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ई-पेंशन कार्ड जारी कर उसे ई-कोष लाइट एप से जोड़ा जाए तथा नियमितीकृत कर्मचारियों की पूर्व सेवा अवधि को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए मान्यता दी जाए। साथ ही पात्र पेंशनरों के 32 माह एवं 27 माह के लंबित एरियर का शीघ्र भुगतान करने की मांग भी दोहराई गई। प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा नए सदस्यों को जोड़ने का आह्वान किया। वहीं प्रदेश संगठन मंत्री टी.पी. सिंह ने संगठन गीत जय हो हिंदुस्तान का सामूहिक गायन कराते हुए कहा कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ का ऐसा संगठन है जिसने राज्य के सभी जिलों में अपना विस्तार किया है और पेंशनरों की आवाज को प्रभावी ढंग से शासन तक पहुंचा रहा है। बैठक में बिलासपुर संभागीय अध्यक्ष राजेन्द्र कश्यप, जिला अध्यक्ष आर.ए. शर्मा, जिला सचिव ठाकुर सुरेन्द्र सिंह, संरक्षक रविशंकर चौबे सहित अनेक पदाधिकारियों और पेंशनरों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने विद्यालय परिसर में कटहल का पौधा लगाकर वृक्षारोपण किया। अंत में सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉ. एस.ई. सिंह के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का संचालन बलराम सिंह तथा आभार प्रदर्शन शंकर साहू ने किया।

25 हजार वोल्ट की OHE लाइन पकड़ने की कर रहा था कोशिश, पावर ब्लॉक लेकर सुरक्षित किया गया रेस्क्यू

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही । पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया। स्टेशन के मेन ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के ऊपर एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक चढ़ गया और ऊपर से गुजर रही 25 हजार वोल्ट की ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ह्॥श्व) लाइन को पकड़ने का प्रयास करने लगा। युवक की इस हरकत से स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई। रेलवे प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और तत्रक्क-त्रक्क की सूझबूझ के चलते समय रहते युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्टेशन कर्मचारियों की नजर जैसे ही मालगाड़ी की छत पर खड़े युवक पर पड़ी, उन्होंने तत्काल रेलवे कंट्रोल को सूचना दी। संभावित खतरे को देखते हुए मेन ट्रैक की विद्युत आपूर्ति बंद कर पावर ब्लॉक लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यदि बिजली सप्लाई समय पर बंद नहीं की जाती, तो युवक हाई-वोल्टेज लाइन की चपेट में आ सकता था।सूचना मिलते ही तत्रक्क और त्रक्क की टीम मौके पर पहुंची। युवक बार-बार आत्महत्या की बात कहते हुए हाई-टेंशन तार पकड़ने की जिद कर रहा था। काफी देर तक समझाइश देने के बाद भी वह नहीं माना। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए मालगाड़ी पर चढ़कर रेस्क्यू अभियान चलाया। युवक को सुरक्षित पकड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके बाद उसे सकुशल नीचे उतार लिया गया।मानसिक रूप से अस्वस्थ है युवकपूछताछ में युवक की पहचान गौरेला क्षेत्र के तरईगांव निवासी के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और घर से बिना बताए निकल गया था। रेस्क्यू के बाद त्रक्क ने युवक को सुरक्षित हिरासत में लेकर उसके परिजनों से संपर्क किया। स्टेशन पहुंचे परिजनों को आवश्यक समझाइश देने के बाद युवक को उनके सुपुर्द कर दिया गया।रेलवे प्रशासन ने इस घटना में सतर्कता दिखाने वाले स्टेशन स्टाफ तत्रक्क और त्रक्क की टीम की तत्परता की सराहना की है। उनकी समय पर की गई कार्रवाई से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया।

जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं

अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने उनसे मिलकर निजी एवं सामुदायिक शिकायत संबंधी आवेदन दिया। उन्होंने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे एवं जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन में पहुंचे ग्राम पंचायत सेंवार के सरपंच दिलहरनलाल रजक ने गांव के विकास और जनसुविधाओं से जुड़े तीन अलग-अलग महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपे हैं। उन्होंने गांव में पर्यावरण संरक्षण और तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए 200 फलदार पौधों की मांग की है, ताकि उन्हें उपयुक्त स्थानों पर लगाया जा सके। इसके साथ ही, सरपंच ने सेंवार के पूर्व माध्यमिक शाला भवन में पढ़ने वाले 228 छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए नए शौचालय और प्रार्थना शेड निर्माण की भी स्वीकृति मांगी है, क्योंकि वर्तमान में वहां बना शौचालय पूरी तरह जर्जर हो चुका है। सरपंच द्वारा एक अन्य ज्ञापन में मुक्तिधाम, छोटकी छुइहा तालाब और साप्ताहिक बाजार स्थल पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने तथा वहां का सीमांकन जल्द से जल्द कराने की मांग की है। ग्राम पंचायत नवागांव सोनसाय के ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर बातया कि गांव के राशन दुकान संचालक द्वारा हितग्राहियों को कम राशन दिया जा रहा है। जांच के दौरान ई-पॉस मशीन से जुड़े कांटे में 20 किलो पर आधा किलो और 35 किलो के वजन पर 800 ग्राम तक की बड़ी गड़बड़ी (कम तौल) पाई गई, साथ ही हितग्राहियों को चने का वितरण भी नहीं किया गया। इसी तरह, ईंट भट्ठे में काम करने वाले तखतपुर तहसील के

नवापारा निवासी भोजराम डहरिया ने अपने परिवार के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़ित मजदूर का कहना है कि उन्होंने कुल 57,158 ईंटें बनाई थीं, जिसके हिसाब से उनकी कुल मजदूरी 59,850 रुपये बनती है, लेकिन भट्ठा मालिक रमेश बंजारे ने उन्हें केवल 36,000 रुपये थमाए और बाकी के 23,850 रुपये देने से साफ मना कर दिया, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर के रानी दुर्गावती खमतराई वार्ड क्रमांक 58 की निवासी श्रीमती वृंदा पटेल ने कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए बताया कि उनका राशन कार्ड बिलासपुर में पंजीकृत है, लेकिन वर्तमान में वह रायगढ़ जिले के डभरा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत ओडेकेरा सराईपाली में रहने लगी हैं। बिलासपुर से रायगढ़ की दूरी अधिक होने के कारण उन्हें राशन लेने और राशन कार्ड संबंधी अन्य कार्यों के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर से अपने राशन कार्ड को रायगढ़ जिले की संबंधित उचित मूल्य दुकान में ट्रांसफर करने का विनम्र आग्रह किया है। मस्तुरी ब्लॉक के ग्राम वृंदावन निवासी दुकेश कुमार पाटले ने बताया कि ग्राम पंचायत डंगनिया के सरपंच हरप्रसाद भारते द्वारा गांव से तीन किलोमीटर दूर आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है। गांव से तीन किलोमीटर दूर होने के कारण छोटे बच्चे या गर्भवती महिलाएं वहां तक पैदल नहीं जा पाएंगी। सरपंच की इस मनमानी पर तुरंत रोक लगाने और आंगनबाड़ी केंद्र को गांव के भीतर ही किसी उपयुक्त स्थान पर बनवाने की मांग की है ताकि बच्चों और महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिल सके।

नई सोच अपनाई, खेती में आई खुशहाली नैनो उर्वरकों से किसान रामकुमार श्रीवास ने घटाई लागत,बढ़ाया उत्पादन

बिलासपुर। तखतपुर विकासखंड के ग्राम सैदा निवासी किसान श्री रामकुमार श्रीवास ने यह साबित कर दिया है कि खेती में बदलाव लाने के लिए बड़े संसाधनों से ज्यादा जरूरी है नई तकनीक पर भरोसा। 10 एकड़ कृषि भूमि पर खेती करने वाले रामकुमार बढ़ती लागत और उत्पादन की चिंता से परेशान थे। ऐसे समय में कृषि विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग शुरू किया। आज यही निर्णय उनकी खेती की सफलता की नई पहचान बन गया है। शुरुआत में उन्हें नई तकनीक को अपनाने में संकोच था। मन में कई सवाल थे कि क्या छोटे पैक में मिलने वाले ये नैनो उर्वरक वास्तव में प्रभावी होंगे। लेकिन कृषि विभाग के विशेषज्ञों की सलाह और वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करने के बाद उनकी सभी शंकाएं दूर हो गईं। फसल की बढ़वार पहले से बेहतर हुई, पौधे अधिक हरे-भरे और स्वस्थ नजर आए तथा पोषक तत्वों का प्रभावी उपयोग होने से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो गई। इसका सीधा लाभ खेती की लागत में कमी के रूप में मिला। रामकुमार श्रीवास बताते हैं कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग से उनकी फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्पादन भी बेहतर मिला। उनका अनुभव है कि

यदि किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार इन उर्वरकों का उपयोग करें, तो कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इससे खेती न केवल लाभकारी बनती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलता है। आज रामकुमार अपने गांव ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं। वे अपने अनुभव साझा करते हुए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और नैनो उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि जब किसान नई तकनीक को खुले मन से अपनाता है, तो खेतों में केवल फसल ही नहीं, समृद्धि भी लहलहाने लगती है।

पंप हाउस कॉलोनी में गुंडागर्दी पर पुलिस का शिकंजा, हत्या के प्रयास का केस दर्ज

- देर रात फ्लैग मार्च और बाइक पेट्रोलिंग, पुलिस का संदेश– बच्चों को पढ़ाओ–लिखाओ, गुंडा न बनाओ

कोरबा। जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के तहत कोरबा पुलिस ने गुंडागर्दी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफसख्त कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में सीएसईबी चौकी क्षेत्र के पंप हाउस कॉलोनी में हुई मारपीट और गुंडागर्दी की घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में जिलेभर में अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अड्डेबाजी, गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था भंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।घटना के बाद शनिवार देर रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी, थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद डडसेना, थाना सिविल लाइन प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी आस्था शर्मा तथा सीएसईबी सहायता केंद्र प्रभारी उप निरीक्षक राजेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस और महिला पुलिस की संयुक्त टीम ने व्यापक बाइक पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्च और सघन चेकिंग अभियान चलाया।अभियान के दौरान पंप हाउस कॉलोनी, 15 ब्लॉक, तुलसी नगर, डीडीएम रोड सहित संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार गश्त की गई। जिन संकरी गलियों में चारपहिया वाहन नहीं पहुंच सकते थे, वहां भी बाइक पेट्रोलिंग कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। देर रात बिना कारण घूम रहे युवकों से पूछताछ कर उनकी पहचान का सत्यापन किया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।कोरबा पुलिस ने कहा है कि संवेदनशील इलाकों में बाइक पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च आगे भी लगातार जारी रहेगा। अड्डेबाजी, हुड़दंग, असामाजिक गतिविधियों और शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे सुरक्षा बल की बड़ी सफलता:करगी रोड डिरेलमेंट मामले में मात्र 10 घंटे के भीतर 10 आरोपी गिरफ्तार....

- सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना का खुलासा, मुख्य आरोपी की तलाश जारी

बिलासपुर। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने करगी रोड रेलवे स्टेशन पर 13 जुलाई 2026 को हुई मालगाड़ी डिरेलमेंट की घटना का त्वरित खुलासा करते हुए मात्र 10 घंटे के भीतर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। रेलवे सुरक्षा बल की इस कार्रवाई में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन एवं तकनीकी साक्ष्यों का प्रभावी उपयोग किया गया। दिनांक 13 जुलाई 2026 को लगभग दोपहर 2:20 बजे करगी रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक-2 स्थित लाइन संख्या-3 पर ह-ङ्गण्×-914 खाली रैक के तीन वैगन डिरेल हो गए थे। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि रेलवे ट्रैक पर जेसीबी मशीन का बकेट आ जाने के कारण यह घटना हुई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त जेसीबी बकेट को इंदौर से करगी रोड तक गाड़ी संख्या 18233 इंदौरङ्कबिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के ए-1 कोच में कोच अटेंडेंट के माध्यम से निजी ठेकेदार पवन नायक (निवासी- करपा, जिला अनूपपुर) द्वारा मंगवाया गया था। करगी रोड स्टेशन पर बकेट को प्लेटफॉर्म क्रमांक-2 पर उतारने के बाद 5-6 मजदूर उसे प्लेटफॉर्म क्रमांक-1 की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान अचानक मालगाड़ी के आने पर मजदूर भारी बकेट को ट्रैक पर ही छोड़कर हट गए, जिससे मालगाड़ी के तीन वैगन डिरेल हो गए। घटना के तत्काल बाद रेलवे सुरक्षा बल ने बिलासपुर से इंदौर तक के रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की। इंदौर रेलवे स्टेशन पर जेसीबी बकेट को नर्मदा एक्सप्रेस के ए-1 कोच में लोड किया जाना पाया गया। इसके पश्चात बिलासपुर स्टेशन पर संबंधित कोच अटेंडेंट को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिससे बकेट को चढ़ाने एवं उतारने वाले व्यक्तियों की पहचान एवं मोबाइल नंबर प्राप्त हुए। मोबाइल लोकेशन एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट उसलापुर द्वारा रेलवे अधिनियम के तहत अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं— 1. कमलेश टेकाम ञ्च मुन्ना (25 वर्ष) 2. नरहर सिंह ञ्च पिंटू (35 वर्ष) 3. देवा सिंह ञ्च मुन्ना (38 वर्ष) 4. बुद्धू सिंह (49 वर्ष)।

अमृत भारत स्टेशन योजना से बदली चांपा जंक्शन रेलवे स्टेशन की तस्वीर

- 13 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ नए स्वरूप में सुसज्जित हुआ चांपा रेलवे स्टेशन

बिलासपुर। रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के रेलवे स्टेशनों का चरणबद्ध तरीके से कायाकल्प किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम एवं यात्री-केंद्रित बनाते हुए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्राप्त हो सके। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल अंतर्गत चांपा रेलवे स्टेशन का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यह स्टेशन स्थानीय कला व संस्कृति की झलक के साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त आकर्षक एवं यात्री-अनुकूल स्वरूप में विकसित हुआ है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में हसदेव नदी के तट पर स्थित चांपा रेलवे स्टेशन हावड़ाङ्कमुंबई मुख्य रेलमार्ग का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। इसकी रणनीतिक एवं व्यावसायिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए स्टेशन का विकास इस प्रकार किया गया है कि यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त हो। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशन परिसर में अनेक आधुनिक एवं यात्री हितैषी सुविधाओं का विकास किया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार एवं सौंदर्यीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण, आकर्षक प्रवेश एवं निकास द्वार, सुव्यवस्थित वाहन पार्किंग, बुकिंग काउंटर का नवीनीकरण, आधुनिक द्वितीय श्रेणी एवं उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय, वीआईपी कक्ष, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, महिलाओं, पुरुषों एवं दिव्यांगजनों के लिए आधुनिक शौचालय, लिफ्ट एवं टैक्टाइल टाइल्स, अत्याधुनिक ट्रेन एवं कोच डिस्प्ले बोर्ड, सीसीटीवी कैमरे, डिजाइनर साइनेज, स्ट्रीट लाइट एवं हाई मास्ट लाइट, बेहतर प्रकाश व्यवस्था तथा यात्रियों के लिए स्टेनलेस स्टील बैठने की व्यवस्था जैसी अनेक सुविधाएं विकसित की गई हैं। इन आधुनिक सुविधाओं से न केवल यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक एवं सुगम यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।

जनहित के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं,समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें:कलेक्टर संजय..

- टीएल बैठक में विकास कार्यों, सीएम हेल्पलाइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा (टीएल) बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित के मामलों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभाग समयसीमा का कड़ाई से पालन करें। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल,वनमंडलाधिकारी श्री नीरज तथा सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की समीक्षा के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कार्यपालन अभियंता को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का केवल औपचारिक नहीं, बल्कि संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले की एकल शिक्षकीय शालाओं में शीघ्र अतिथि

शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं भी अतिथि शिक्षक के रूप में ली जा सकती हैं, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। कलेक्टर ने जर्जर स्कूल भवनों में किसी भी स्थिति में कक्षाएं संचालित नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे विद्यालयों के लिए तत्काल वैकल्पिक भवनों की व्यवस्था की जाए तथा नए भवन अथवा अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि डीएमएफके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए उपलब्ध प्रावधानों का प्रभावी उपयोग किया जाए। बैठक में यह भी बताया गया कि डीएमएफ के माध्यम से विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्तियों के लिए सहमति प्रदान की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शेष किसानों का सत्यापन 15 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी कार्यालयों में इसकी शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि जल्द ही बायोमेट्रिक उपस्थिति को वेतन भुगतान से जोड़ा जाएगा।बैठक में 18 जुलाई को प्रस्तावित जिलेव्यापी वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

गुप्त नवरात्रि में नहीं करने चाहिए ये काम

हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। वर्ष में कुल चार बार नवरात्रि आती है. इनमें से दो को प्रकट नवरात्रि और दो को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रकट नवरात्रियों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधिपूर्वक पूजा की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना और 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से साधकों और तांत्रिक साधनाओं से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस वर्ष आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 से शुरू होकर 23 जुलाई 2026 तक चलेगी।

गुप्त नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये गलतियां

तामसिक भोजन का परहेज करें
इस दौरान मांसाहार, लहसुन-प्याज और शराब जैसे तामसिक आहार पूरी तरह से वर्जित माने जाते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें।

ज्वार न बोएं

सामान्य नवरात्रि में घटस्थापना के समय ज्वार बोने की परंपरा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में इसे वर्जित माना गया है। ऐसा करना पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकता है।

रौद्र रूप की मूर्ति या तस्वीर न लगाएं

मां के उग्र या रौद्र रूपों की तस्वीर गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजन स्थल पर न लगाएं। इससे साधना में विघ्न आ सकता है।

दक्षिण दिशा की यात्रा न करें

गुप्त नवरात्रि के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा को अशुभ माना जाता है। संभव हो तो इस दिशा में जाने से बचें।
गुप्त नवरात्रि की साधना बेहद शक्तिशाली मानी जाती है, लेकिन इसके साथ ही यह अनुशासन और सावधानी की भी मांग करती है। जो साधक विधिवत और नियमपूर्वक इसका पालन करते हैं, उन्हें मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

कब से शुरू होगी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि?

तिथि और घटस्थापना मुहूर्त

आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। वहीं, गुप्त नवरात्रि में देवी की दस महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस दौरान तांत्रिक, अघोरी तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे में गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत विशेष होता है। इस दौरान देवी की साधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है।

आषाढ़ मास आरंभ हो चुका है। इस महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। पूरे वर्ष में चार नवरात्रि आती हैं, जिनमें से एक गुप्त नवरात्रि होती है। हिंदू धर्म में इन नौ दिनों का बहुत खास महत्व होता है। एक गुप्त नवरात्रि माघ में भी आती है। मान्यता है कि ये नवरात्रि सिद्धि और साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। साथ ही, तंत्र मंत्र के साधक की इन दिनों में विशेष रूप से साधना रखते हैं। गुप्त नवरात्रि लोगों के बीच ज्यादा प्रचलित नहीं है, जिसके पीछे का कारण यही है कि इसमें तंत्र मंत्र के साधक ज्यादा साधना रखते हैं। माना जाता है कि इस दौरान मां दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है।

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तिथियां

साल 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से शुरू होकर 22 जुलाई तक रहेगी। इसके बाद 23 जुलाई को व्रत का पारण किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार तीसरा और चौथा नवरात्र एक ही दिन, 17 जुलाई को पड़ रहा है।

घटस्थापना का शुभ समय

आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 जुलाई को दोपहर 03:12 बजे आरंभ होकर 15 जुलाई को सुबह 11:50 बजे समाप्त होगी। ऐसे में घटस्थापना का शुभ मुहूर्त 15 जुलाई 2026 को सुबह 05:33 बजे से 10:09 बजे तक रहेगा।

गुप्त नवरात्रि का महत्व

धार्मिक दृष्टि से गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दौरान किए गए व्रत और साधना से भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। प्राचीन समय में इस नवरात्रि का ज्ञान केवल ऋषि-मुनियों और साधकों तक सीमित था। वे इस काल में दस महाविद्याओं की उपासना कर विशेष आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास करते थे।

आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि नियम

माना जाता है कि भूलकर भी गुप्त नवरात्रि में तामसिक भोजन जैसे- मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही, इस अवधि के दौरान मदिरा से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार के क्रोध व विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बाल और नाखून काटने भी वर्जित माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में गलती से भी ये दो कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में भूलकर भी चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल नही करना चाहिए। साथ ही, इससे बनी चीजों को धारण भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है।
कहा जाता है नवरात्रि में दिन के समय सोना और बिस्तर पर सोना भी वर्जित होता है। खासतौर पर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की साधनाआषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में सामान्य लोग मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा, तांत्रिक, अघोरी तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये सभी देवी की दस महाविद्याओं की साधना करते हैं, जिन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर देवी की कृपा होती है, उसे किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही, ऐसे लोगों के लिए दुनिया मे कुछ भी असंभव नही रहता है। देवी की दस महाविद्याएं इस प्रकार हैं- माता धूमावती देवी, माता काली देवी, माता त्रिपुरा देवी, तारा देवी, माता षोडशी देवी, माता छिन्नमस्ता देवी, भुवनेश्वरी देवी, माता बगलामुखी देवी, माता कमला देवी और माता मातंगी देवी।

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर 12 साल बाद दुर्लभ योग

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है. इसका समापन 23 जुलाई को होगा. इस बार गुप्त नवरात्र 9 दिन की होंगी. तांत्रिक साधना के लिए ये समय अचूक माना जाता है. मार्कण्डेय पुराण (दुर्गा सप्तशती), देवी भागवत महापुराण, रुद्रयामल तंत्र, शक्तिसंगम तंत्र, तंत्रसार आदि शाक्त ग्रंथों में गुप्त नवरात्रि का वर्णन मिलता है. इस नवरात्रि में साधक अपनी साधना को गोपनीय रखते हैं. इस बार गुप्त नवरात्रि पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं।

12 साल बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग

इस वर्ष गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ अत्यंत शुभ और दुर्लभ ज्योतिषीय संयोगों के बीच हो रहा है. 15 जुलाई को बुधवार के दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान होंगे. इसी दौरान चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी योग का निर्माण होगा. चूंकि गुरु लगभग 12 वर्ष बाद पुनः इसी राशि में आते हैं, इसलिए यह संयोग विशेष महत्व रखता है. इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत गजकेसरी योग और बुध-पुष्य योग के शुभ संयोग में होगी, जो साधना, मंत्र सिद्धि और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है. इतना ही नहीं, पूरे गुप्त नवरात्रि काल में 2 सर्वार्थ सिद्धि योग और 3 रवि योग भी बनेंगे, जिससे इस पर्व का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व कई गुना बढ़ जाएगा.

किन देवियों की होती है पूजा

शत्रु बाधा, ग्रह दोष और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए गुप्त नवरात्रि में दशमहाविद्याओं काली, तारा, त्रिपुरसुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की विशेष उपासना की जाती है.

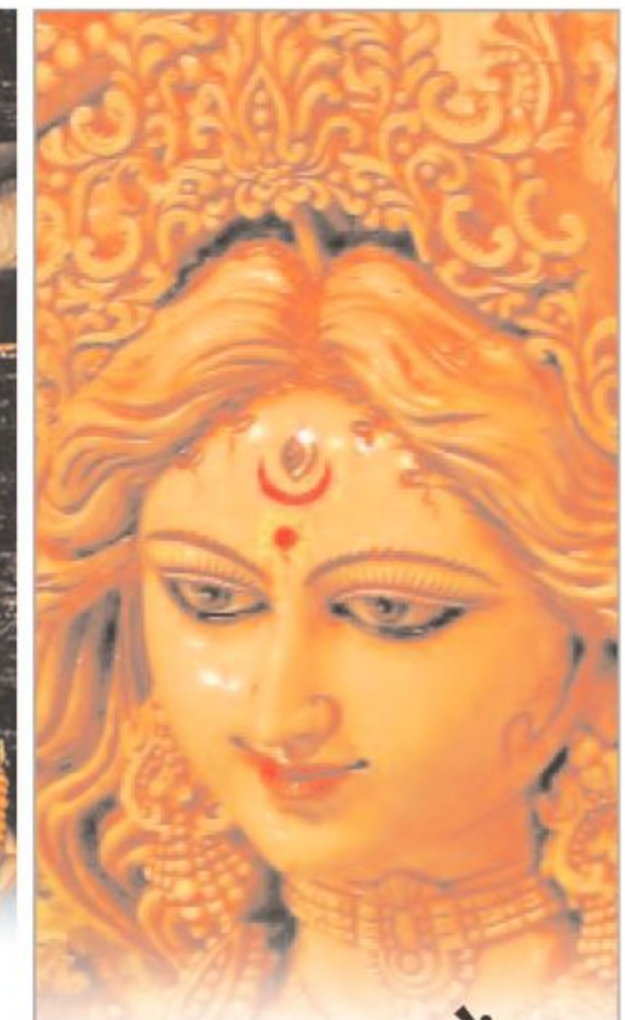

गुप्त नवरात्र में इन बातों का रखें ध्यान

गुप्त नवरात्र का पर्व सनातन धर्म में बहुत शुभ माना जाता है जो मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। इस दौरान देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और रोग-दोष दूर होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गुप्त नवरात्र कब शुरू होगी?

सनातन धर्म में नवरात्र का पर्व बहुत शुभ माना जाता है। यह मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा के लिए समर्पित है। गुप्त नवरात्र को तंत्र-मंत्र और गुप्त सिद्धियों के लिए विशेष माना जाता है। इस दौरान देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि इस दौरान कठिन उपवास करने से सभी तरह के रोग-दोष दूर होते हैं।

15 जुलाई से शुरू होगी गुप्त नवरात्र

साल 2026 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 से शुरू होकर 23 जुलाई 2026 तक चलेगी। यह साधना, तंत्र-मंत्र और देवी दुर्गा की दस महाविद्याओं की उपासना के लिए अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली मानी जाती है।

इन बातों का रखें ध्यान

- इन नौ दिनों में मांसाहार, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें।
- नवरात्र के दौरान बाल और नाखून काटने से बचें।
- चमड़े से बनी वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स आदि का प्रयोग न करें।
- घर में शांति और सकारात्मक माहौल बनाए रखें।
- लड़ाई-झगड़े, बहस और अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें।
- व्रती दिन में सोने से बचें।
- मन में किसी के प्रति बुरे विचार न लाएं।
- इन नौ दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें।
- देवी की पूजा पूरे विधि-विधान से करें।
- पूजा सामग्री और विधि में किसी भी तरह की कमी न छोड़ें।
- स्त्री का अपमान भूलकर भी न करें।

मां की 8 भुजाएं, त्रिनेत्र क्यों हैं किस चीज का देते हैं संकेत

गुप्त नवरात्र आषाढ़ माह में 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के हर रूप की अपनी विशेषता है। उनकी आठ भुजाएं हर दिशा से भक्तों की रक्षा करने का संकेत देती हैं जिनमें अलग-अलग अस्त्र और शस्त्र होते हैं।

गुप्त नवरात्र माघ और आषाढ़ माह में मनाए जाते हैं। इस साल अषाढ़ के गुप्त नवरात्र 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। नवरात्र के 9 दिन मां के नौ रूपों की पूजा की जाती है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ावाली विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। मां दुर्गा ने ये 9 रूप अलग-अलग वजहों से लिए। हर रूप में वह भक्तों का कल्याण करती हैं। इन नौ दिनों में अखंड ज्योति जलाकर मां का ध्यान और आराधना करने से समस्त दुखों का नाश होता है। इस मौके पर चलिए जानते हैं उनके रूप में उनकी भुजाओं, त्रिनेत्र का क्या संकेत है।

मां दुर्गा के हैं 9 रूप

नवरात्रि में हर दिन मां दुर्गा के अलग रूप की पूजा की जाती है। उनके नौ रूप नौ महाविद्याओं को दर्शते हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवां स्कंदमाता, छठवां कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौंवा सिद्धिदात्री का रूप उन्होंने लिया है। हर रूप एक खास गुण और शक्ति का प्रतीक है।

शक्ति के बिना अधूरे हैं शिव

शिव और शक्ति एक-दूसरे के पूरक है। दोनों के मिलन से ही सृष्टि की रचना और संचालन होता है। शिव के बिना शक्ति निष्क्रिय हैं, और शक्ति बिना शिव के स्थिर नहीं हो सकते हैं। शिव जहां स्थिरता, ध्यान, और संहारक के रूप में जाने जाते हैं। वहीं, शक्ति, शिव की ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार का कारण बनती हैं।

आठ दिशाओं से करती हैं रक्षा

मां दुर्गा की मूर्तियों में 8 हाथ दिखाए जाते हैं। हर हाथ में अलग-अलग अस्त्र और शस्त्र होते हैं, जो बुराई से लड़ने के प्रतीक के रूप में दिखाए जाते हैं। मां की अष्ट भुजाएं यह संकेत देती हैं कि वह अपने भक्तों की हर दिशा से रक्षा करती हैं। वह 'त्रिनेत्रधारी' भी कही जाती है। उनकी बाईं आंख चंद्रमा का प्रतीक है, जो शांति और प्रेम से परिपूर्ण है। दाईं आंख सूर्य का प्रतीक जो ऊर्जा और शक्ति देती है। वहीं, तीसरी आंख अग्नि का प्रतीक है, जो बुराई को नष्ट करने वाली ताकत का प्रतीक है।

शिवनाथ नदी मुक्तिधाम का होगा कायाकल्प, 26.23 लाख रुपए के जीर्णोद्धार कार्य का महापौर ने किया भूमिपूजन

मुक्तिधाम में शेड, सड़क, पेवर ब्लॉक, शौचालय सहित कई सुविधाओं का होगा विस्तार : महापौर

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक-01 स्थित शिवनाथ नदी मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार कार्य का आज महापौर अलका बाघमार ने भूमिपूजन किया। 26.23 लाख रुपए की लागत से होने वाले इस महत्वपूर्ण विकास कार्य के अवसर पर सभापति श्याम शर्मा, लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, एमआईसी सदस्य एवं वार्ड पार्षद मनीष साहू सहित जनप्रतिनिधि एवं वार्डवासी उपस्थित रहे। शिवनाथ नदी मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार कार्य के तहत नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे। इसमें लकड़ी रखने के लिए शेड निर्माण, पेवर ब्लॉक बिछाने का कार्य, सड़क निर्माण, पुरानी परिसीमा दीवार का ध्वस्तीकरण, पुराने प्रवेश द्वार के समीप शौचालय ब्लॉक निर्माण एवं पुराने शवदाह शेड के पास कचरा संग्रहण टैंक का निर्माण शामिल है। इन कार्यों के पूर्ण होने से मुक्तिधाम की व्यवस्था बेहतर एवं सुविधाजनक होगी। भूमिपूजन के दौरान महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर के सभी वार्डों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। मुक्तिधाम जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का व्यवस्थित विकास आवश्यक है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों की श्रृंखला जारी है और जनहित से जुड़े कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में एमआईसी सदस्य नरेंद्र बंजारे, लीना दिनेश देवांगन, काशीराम कोसरे, गुलाब वर्मा, मनीष साहू, रामचंद्र सेन, जितेंद्र महोबिया, सुरूचि उमरे, रंजीता पाटिल, जिला भाजपा प्रवक्ता अरुण सिंह, मनमोहन सिंह, अनूप सोनी, चमेली साहू, तुलसी यादव, सहायक अभियंता संजय ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं निगम अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सुपेला रावणभाठा में तोड़फोड़ पर विधायक रिकेश सेन नाराज़, बोले– बरसात में बिना सूचना कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

भिलाई नगर। भिलाई के सुपेला स्थित रावणभाठा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बुलडोजर चला कर 40 से अधिक दुकानों को हटाने की कार्रवाई के बाद वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने नाराज़गी जताई है।

विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद जैसे ही उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी मिली, उन्होंने निगम अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए।

विधायक रिकेश सेन ने कहा कि बरसात के मौसम में इस प्रकार की कार्रवाई से प्रभावित परिवारों और दुकानदारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी बड़ी कार्रवाई से पहले स्थानीय विधायक को विश्वास में लेना चाहिए था,

लेकिन निगम अधिकारियों ने बिना किसी सूचना के मनमाने ढंग से कार्रवाई कर दी।

उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण हटाने जैसी कार्रवाई आवश्यक भी थी, तो इसके समय और तरीके पर संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए थी। बरसात के बीच लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित करने वाली कार्रवाई उचित नहीं कही जा सकती।

विधायक ने स्पष्ट कहा कि बिना विधायक को जानकारी दिए और जनहित की अनदेखी कर कार्रवाई करने वाले जिम्मेदार निगम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। जनता के हितों की रक्षा उनकी प्राथमिकता है और किसी भी अधिकारी को मनमाने तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गौरतलब है कि नगर निगम ने रावणभाठा क्षेत्र में कथित अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए 40 से अधिक दुकानों को हटाया। बताया जा रहा है कि प्रभावित लोगों को तीन दिन पहले नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, कार्रवाई के समय को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष देखने को मिला है।

विश्व जनसंख्या दिवस पर संगोष्ठी पोस्टर एवं क्विज प्रतियोगिता आयोजित

दुर्ग। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संगोष्ठी, पोस्टर, भाषण एवं ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महापौर मती अलका बाघमार, विशेष अतिथि जिला पंचायत सदस्य सु प्रिया साहू तथा अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी ने की। इस अवसर पर जिला नोडल अधिकारी (मातृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) डॉ. अर्चना चौहान एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अजय सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने बढ़ती जनसंख्या से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं

संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से जनसंख्या संतुलन, स्वस्थ परिवार-सुरक्षित भविष्य तथा संसाधनों के संतुलित उपयोग का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि मती अलका बाघमार ने अपने संबोधन में कहा कि बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों से निपटने के लिए जनजागरूकता, शिक्षा और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। वहीं विशेष अतिथि सु प्रिया साहू ने समाज में व्याप्त दुष्कर्म जैसी गंभीर समस्या पर विचार व्यक्त करते हुए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में पोस्टर, भाषण एवं ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मती मीना मान, मती शोभिका गजपाल, डॉ. अमरीश त्रिपाठी, तरुणा साहू, डॉ. सीमा पंजवानी सहित महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कृषि इनपुट की सुगम उपलब्धता से समृद्ध हो रहे कृषक

समय पर यूरिया व उन्नत खाद मिलने से फसल चक्र हुआ सुदृढ़

दुर्ग। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के आर्थिक संवर्धन और कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में, खरीफ सीजन के दौरान कृषकों को आवश्यक कृषि आदान (कृषि इनपुट) सामग्री उपलब्ध कराने के लिए धरातल पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन दुर्ग की सतत मॉनिटरिंग के फलस्वरूप ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक साख सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विज्ञान के दृष्टिकोण से यूरिया और अन्य खाद फसलों की प्रारंभिक वानस्पतिक वृद्धि, क्लोरोफिल निर्माण और समुचित विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं, जो फसल की उत्पादकता व गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। दुर्ग विकासखंड के ग्राम जेवरा निवासी प्रगतिशील कृषक कमलेश कुमार साहू ने बताया कि उन्हें

सिरसा स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से अपनी आवश्यकता के अनुरूप दो चरणों में यूरिया खाद एवं उन्नत बीज अत्यंत सुगमता से प्राप्त हो गए हैं। खेती-किसानी के इस संवेदनशील समय में कृषि आदानों की त्वरित उपलब्धता से खेतों में बुआई और पोषण प्रबंधन का कार्य बिना किसी मानसिक व आर्थिक तनाव के समय पर पूरा हो सका है। कृषक साहू ने अपने पिछले अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि पूर्व में किसानों को खादों के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, जिससे समय नष्ट होता था और फसल भी प्रभावित होती थी। किंतु इस वर्ष प्रशासनिक व्यवस्था के कारण यूरिया और बीज बिना किसी परेशानी के सीधे किसानों तक सहजता से पहुंच रहे हैं। समयबद्ध तरीके से मुख्य पोषक तत्वों की आपूर्ति होने से फसलों के स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार देखा जा रहा है, जिससे आगामी समय में बंपर पैदावार की ठोस उम्मीद जगी है। शासन की इस किसान-हितैषी नीति और पारदर्शी वितरण प्रणाली से अभिभूत होकर कृषक कमलेश कुमार साहू ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन दुर्ग के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि खाद-बीज की निर्बाध उपलब्धता से जिले के कृषक समुदाय का मनोबल ऊंचा हुआ है और वे पूर्ण उत्साह के साथ खरीफ सीजन की खेती में संलग्न हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026

दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन और कृषकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया गया है। मौसम खरीफ वर्ष 2026 प्रारंभ हो चुका है और अल-नीनो के प्रभाव के कारण मौसम की असामान्य परिस्थितियां (अल्प/ अतिवृष्टि) निर्मित होने की प्रबल संभावना है, जिससे खरीफ फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2026 हेतु ऐसे किसान जो अब तक फसल बीमा नहीं कराये है उनका पंजीयन राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है। संभागीय संयुक्त संचालक कृषि द्वारा संभाग के समस्त जिलों के ऋणी/अऋणी किसानों को अधिक से

अधिक संख्या में निकटस्थ सहकारी समितियों, बैंक, च्वाईस सेंटर के माध्यम से तत्काल संपर्क कर फसल बीमा कराने हेतु अपील की गई है, ताकि कोई भी पात्र केसीसी धारी कृषक बीमा आवरण से वंचित न हो। संयुक्त संचालक कृषि ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं (स्थानीयकृत आपदा एवं फसल कटाई उपरांत क्षति) से होने वाले फसल नुकसान की त्वरित राहत और निराकरण के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 को प्रभावी रूप से लागू किया गया है।

आईएएस सुरूचि सिंह ने नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त का पदभार ग्रहण किया

भिलाईनगर। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सुरूचि सिंह ने सोमवार को नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। राज्य शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के तहत उन्हें नगर पालिक निगम भिलाई का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व वे जिला पंचायत राजनांदगांव की मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थीं। नगर निगम मुख्यालय पहुंचने पर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सिंह का आत्मीय स्वागत किया। आयुक्त सुरूचि सिंह का शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक तक पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। पदभार ग्रहण के दौरान निगम के सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने नवपदस्थ आयुक्त का स्वागत करते हुए उन्हें निगम की वर्तमान परियोजनाओं एवं विभिन्न विभागों की प्रगति से अवगत कराया। राज्य शासन द्वारा हाल ही में किए गए प्रशासनिक फेरबदल के अंतर्गत आईएएस अधिकारी सुरूचि सिंह को नगर पालिक निगम भिलाई का आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनके प्रशासनिक अनुभव एवं कार्यकुशलता से भिलाई नगर निगम में विकास कार्यों को नई दिशा एवं गति मिलेगी।

विश्व जनसंख्या दिवस पर दुर्ग जिले में चला व्यापक विधिक जागरूकता अभियान'

दुर्ग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के परिपालन में विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला, कोलिहापुरी एवं पुलगांव उच्च माध्यमिक शाला में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी विरेन्द्र सिंह, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी आरती ध्रुव एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी प्रियंका गोस्वामी तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के दो काउंसलर विशेष रूप से उपस्थित रहे। पुलगांव उच्च माध्यमिक शाला में आयोजित कार्यक्रम में न्यायाधीशों का विद्यालय परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात उन्होंने विद्यार्थियों को विश्व जनसंख्या दिवस के इतिहास, उद्देश्य एवं महत्व से अवगत कराया। इसके साथ ही कानून

के प्रति जागरूकता, यातायात नियमों के पालन, कैरियर निर्माण तथा पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक और ओटीपी साझा करने के खतरों के बारे में भी जागरूक किया गया तथा साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय बताए गए। शासकीय माध्यमिक शाला, कोलिहापुरी में आयोजित शिविर में LADCS के काउंसलरों ने विद्यार्थियों को विश्व जनसंख्या दिवस के महत्व, नशामुक्ति, गुड टच एवं बैड टच तथा बाल संरक्षण संबंधी कानूनों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने, बिना हेलमेट एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाने तथा साइबर अपराधों से सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अनेक प्रश्न पूछे, जिनका उपस्थित न्यायाधीशों एवं काउंसलरों ने सरल एवं प्रेरणादायक ढंग से उत्तर दिया।

शिक्षकों की कमी से जूझ रहा पी एम श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय कुम्हारी, कक्षा 1 से 5 तक बच्चों की एक दिन छोड़कर लग रही कक्षाएं

कुम्हारी। नगर पालिका परिषद कुम्हारी स्थित पी एम स्वामी आत्मानंद विद्यालय इन दिनों शिक्षकों की कमी और सीमित संसाधनों के कारण अव्यवस्था का सामना कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि कक्षा पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं एक दिन छोड़कर संचालित की जा रही हैं। सोमवार को यदि 'ए' सेक्शन के बच्चे विद्यालय आते हैं तो 'बी' सेक्शन के विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाई जाती हैं।सोमवार को भी यही व्यवस्था रही। यह व्यवस्था पिछले लगभग एक सप्ताह से जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यालय में 1600 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें लगभग 1100 छात्र-छात्राएं अंग्रेजी माध्यम तथा करीब 500 विद्यार्थी हिंदी माध्यम में अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में नए प्रवेश की प्रक्रिया भी जारी है। इस शैक्षणिक सत्र से बालवाड़ी कक्षाओं का भी शुभारंभ किया गया है, जिससे विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या और बढ़ गई है। संस्था से मिली

जानकारी के अनुसार विद्यालय में वर्तमान में 39 शिक्षक पदस्थ हैं, जबकि सुचारु संचालन के लिए लगभग 50 शिक्षकों की आवश्यकता बताई जा रही है। यानी विद्यालय में 11 शिक्षकों की कमी है। एक ही परिसर में सभी कक्षाओं का संचालन होने के कारण उपलब्ध शिक्षकों के माध्यम से समायोजन कर अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। विद्यालय परिसर में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से भवन अभी तक विद्यालय प्रबंधन को हैंड ओवर नहीं किया गया है। इसके कारण नई कक्षाओं का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है और विद्यार्थियों को पर्याप्त कक्ष उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। हालांकि विद्यालय का संचालन दो पालियों में किया जा रहा है, जिससे व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। बावजूद इसके शिक्षकों की कमी और अतिरिक्त कक्षों के अभाव का असर विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई पर पड़ रहा है। स्थानीय अभिभावकों एवं नागरिकों ने शासन-प्रशासन से शीघ्र अतिरिक्त शिक्षकों की पदस्थापना तथा नए भवन को विद्यालय के सुपुर्द कर कक्षाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित करने की मांग की है।

कलेक्टर ने संबंधित विभागों को दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश

समय-सीमा की बैठक : जनहित की कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

बलरामपुर। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों एवं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा जनहित से जुड़े सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में वीबी जी रामजी के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए अधिक से अधिक रोजगार स्वीकृत करने एवं पात्र हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने नियमित रूप से मैदानी भ्रमण कर कार्यों की वास्तविक स्थिति का अवलोकन कर कार्यों कि गुणवत्ता एवं प्रगति सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान की समीक्षा करते हुए बेहतर प्रबंधन एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने

अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पुनर्वास नीति-2025 के तहत प्रत्येक पात्र हितग्राही तक शासन की योजनाओं का लाभ सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए,ताकि कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं से वंचित न रहे। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने प्रधान पाठकों एवं शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर मध्यान्ह भोजन में हरी सब्जी उपलब्ध कराने तथा सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए,जिससे व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। कलेक्टर ने बैग पाठ्यपुस्तकों एवं गणवेश का वितरण सरस्वती साइकिल योजना का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने जाति एवं आय प्रमाण-पत्र शिविरों का सफलतापूर्वक संचालन करने के निर्देश दिए। स्कूल जतन योजना के अंतर्गत नवीन शौचालय निर्माण, वर्ष 2024-25 के पूर्ण कार्यों का मैदानी सत्यापन तथा अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने साथ ही वर्ष 2025-26 के स्वीकृत कार्यों में तेजी लाने को कहा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए,ताकि आमजन की सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने खाद एवं बीज की उपलब्धता, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रकरणों तथा विकासखंडवार एग्रीस्टैक पंजीयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए पंजीयन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजी पोर्टल तथा कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त लंबित शिकायतों एवं आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा सहित लंबित राजस्व प्रकरणों तथा लंबित पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर आर.एस. लाल, प्रमोद गुप्ता, आर.एन. पाण्डेय, सर्व अनुविभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सेवा सेतु से आसान हुई प्रक्रिया : अजय को मिला मूल निवासी प्रमाण पत्र

दुर्ग। पाटन निवासी अजय चन्द्राकार को अपने विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। पहले उन्हें यह चिंता थी कि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन की सेवा सेतु पहल ने उनकी यह चिंता पूरी तरह दूर कर दी। अजय चन्द्राकार ने 14 मई 2026 को तहसील कार्यालय पाटन स्थित सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक रही। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 28 मई 2026 को उनका मूल निवासी प्रमाण पत्र समय पर जारी कर दिया गया। सेवा सेतु के माध्यम से उन्हें घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिली, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत हुई। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही और बिना किसी अनावश्यक परेशानी के प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। अब वे इस प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न शासकीय एवं अन्य आवश्यक कार्यों में आसानी से कर पा रहे हैं। अपने अनुभव को साझा करते हुए अजय चन्द्राकार ने कहा, सेवा सेतु के माध्यम से मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ही सरल और सुविधाजनक रहा। बिना किसी परेशानी के समय पर प्रमाण पत्र मिल गया।ष् उन्होंने कहा सेवा सेतु है तो भरोसा है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com